▸▸ कृषि ▸▸ विश्लेषण ▸▸ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

भाद्रपद–अश्विन 2082, सितंबर 2025

जीएसटी में अभूतपूर्व सुधार

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी बैठकें

सचित्र झलक

स्वदेशी संगोष्ठी, भोपाल, म.प्र.

क्षेत्रीय बैठक, जोधपुर, राज.

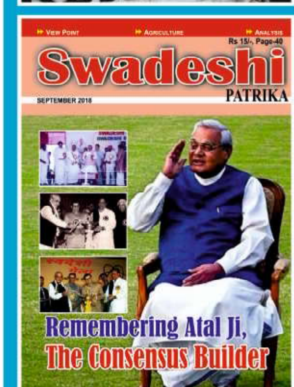

VOICE OF

SELF RELIANT INDIA

SWADESHI
Patrika

स्वदेशी
पत्रिका

पढ़ें और पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

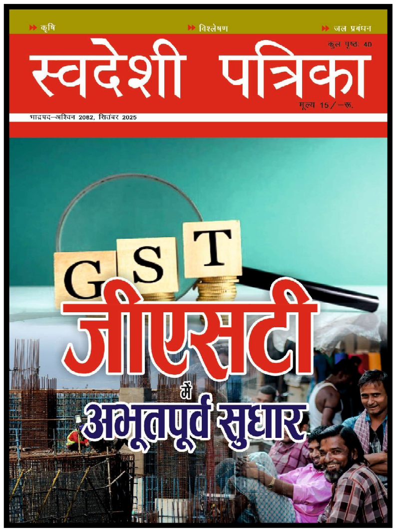

वर्ष–33, अंक–9

भाद्रपद–अश्विन 2082 सितंबर 2025

संपादक

अजेय भारती

सह–संपादक

अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4

समाचार परिक्रमा 36-38

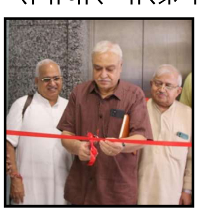

तृतीय मुख्य पृष्ठ 39

चतुर्थ मुख्य पृष्ठ 40

आवरण कथा – पृष्ठ–06

जीएसटी में अभूतपूर्व सुधार

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ

2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आवरण कथा–2

सुधार से आसान होती विकसित अर्थव्यवस्था की राह .... *अनिल तिवारी*

10 आर्थिकी

भारत का विदेशी व्यापार और आत्मनिर्भरता .... *अनिल जवलेकर*

12 विज्ञान

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढते कदम .... *दुलीचंद कालीरमन*

14 प्राकृतिक हलचल

आपदाओं से त्रस्त उत्तराखंड .... *विनोद जौहरी*

16 जन्मदिन पर विशेष

साधारण से असाधारण बने नरेन्द्र मोदी .... *अजय कुमार*

18 योजना

सबको पक्का घर का सपना साकार करती प्रधानमंत्री आवास योजना .... *शिवनंदन लाल*

20 समीक्षा

अमरीका से आयी आपदा को अवसर में बदलने का मौका है भारत के पास .... *डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र*

22 दृष्टिकोण

मर्यादित अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है पारिवारिक गौरव .... *प्रो. गौरी पिंपले*

24 भारतीय दर्शन

वर्तमान वैश्विक नेतृत्व में विश्व कल्याण के भाव का अभाव .... *प्रहलाद सबनानी*

26 मुद्दा

प्रकृति से खिलवाड़ के खतरनाक नतीजे .... *विजय गर्ग*

28 विचार विमर्श

भावनाएं भड़काने वाली राजनीति से रहना होगा सावधान .... *संध्या जैन*

30 पुस्तक समीक्षा

वैज्ञानिक और दार्शनिक चेतना की गांठें खोलता है 'कालजयी भारतीय ज्ञान' .... *नवनीत शर्मा*

32 आधी–आबादी

बहु–आयामी अवधारणा है महिलाओं का सशक्तिकरण .... *स्वदेशी संवाद*

34 धरम–करम

शक्ति के नौ रूपों की उपासना का पर्व है शारदीय नवरात्र .... *संजय सक्सेना*

पाठकनामा

जीएसटी हुआ सरलः आमजन को दीपावली का तोहफा

भारत में हाल के जीएसटी सुधारों का आम जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसका उद्देश्य वस्तुएं और सेवाएं सस्ती बनाना, टैक्स–संरचना को सरल बनाना और समाज के हर वर्ग में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। सरकार ने दो स्लैब जीएसटी (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) अपनाया है, जिसमें साबुन, ब्रेड, टूथपेस्ट जैसी ज़रूरी चीजों पर टैक्स 5 प्रतिशत या शून्य कर दिया गया है। इससे खासकर मध्यम वर्ग, किसानों और एमएसएमई के घरेलू खर्च सीधे घटे हैं और उनकी बचत बढ़ी है। जीवनरक्षक दवाएं, स्वास्थ्य बीमा और कृषि उपकरणों पर भी दरें काफी घटाई गई हैं, जिससे सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच व्यापक हुई है।

इन सुधारों की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पूर्ववर्ती जीएसटी संरचना जटिल थी– इसमें 28 प्रतिशत तक के कई स्लैब थे, जिससे भ्रम, नियमों में बार–बार बदलाव और छोटे कारोबारियों तथा उपभोक्ताओं के लिए अनुपालन का दबाव बढ़ता गया। एमएसएमई को वर्गीकरण, तकनीकी दिक्कतों और उच्च लागत का सामना करना पड़ता था, जिससे उद्यमिता पर असर पड़ता था और स्थानीय खपत घटती थी। अब स्लैब कम करने से अनुपालन आसान हुआ है, उपभोक्ता मांग बढ़ी है, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में सस्ता माल उपलब्ध हुआ है, और यह भारत के त्योहार सीजन के साथ शुरू किया गया है, जिससे इसका "दिवाली गिफ्ट" जैसा प्रभाव पड़ रहा है।

सरकार का मूल उद्देश्य नागरिक–केंद्रित सुधार हैः जीवन को सरल बनाना, मांग को बढ़ाना, निर्माताओं को समर्थन देना और अंततः "स्वावलंबी भारत" के बड़े विज़न के अनुरूप आगे बढ़ना। संक्षेप में, जीएसटी सुधार रोजमर्रा की ज़रूरतें सुलभ बनाते हैं, राष्ट्रीय विकास को मजबूती देते हैं और पुरानी व्यवस्था की कमियों की प्रतिक्रिया में सच्चा वित्तीय राहत देकर आम परिवारों को भारत की समृद्धि यात्रा में भागीदार बनाते हैं।

विजित कुमार (स्वदेशी कार्यकर्ता), दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

दुनिया भारत पर भरोसा करती है। विश्व भर के देश भारत के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भविष्य बनाने के लिए तैयार है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

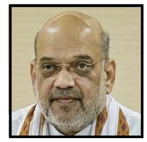

हमारा देश मूलतः एक भाषा–प्रधान राष्ट्र है। हमारी भाषाएँ संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी–दर–पीढ़ी आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम रही हैं।

अमित शाह, गृहमंत्री, भारत

जब भारत एकजुट परिवार की तरह काम करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में एक–दूसरे को सहयोग देगा, तो समावेशी विकास स्वाभाविक रूप से होगा।

पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत

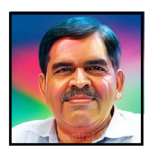

स्वदेशी का मतलब आयात या निर्यात को रोकना नहीं है – इसका मतलब कुशलतापूर्वक और नवीनतापूर्वक वस्तुओं का उत्पादन करना है ताकि वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

डॉ. अश्वनी महाजन, अ.भा.सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

आज और भी प्रासंगिक हैं पं. दीनदयाल उपाध्याय

पिछले सौ वर्षों में दुनिया ने प्रौद्योगिकी, भौतिक वस्तुओं के उत्पादन और आर्थिक सेवाओं के विस्तार के मामले में अभूतपूर्व प्रगति की है। अगर हम इस प्रगति को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संदर्भ में मापें, तो हम पाते हैं कि पिछले सौ वर्षों में दुनिया की जीडीपी कई गुना बढ़ गई है। विभिन्न चरणों में हुई औद्योगिक क्रांतियों ने इस भौतिक विकास में योगदान दिया है। आम तौर पर लोग अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। बुनियादी ढाँचे, ऑटोमोबाइल, विमानन, अंतरिक्ष, संचार आदि के क्षेत्र में प्रगति सबसे उल्लेखनीय रही है। लेकिन साथ ही, पर्यावरण क्षरण, आर्थिक असमानताओं और सामाजिक विघटन के कारण मानवता ने अपने अस्तित्व के मूल आधार को ही संकट में डाल दिया है। हमारा समाज और व्यवस्था उस स्तर पर पहुँच गई है जहाँ हम देखते हैं कि अगर इन बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया तो मानव सभ्यता ही नहीं सृष्टि से जीवन ही विलुप्त हो सकता है। वर्तमान बुराइयों का मूल कारण यह है कि हमने यह मान लिया है कि यदि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है, यदि अधिक ऊर्जा खपत होती है और जीडीपी बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि विकास हो रहा है। यह भी मान लिया गया कि इस भौतिक प्रगति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का स्वतः ही समाधान हो जाएगा, क्योंकि इस बढ़े हुए उत्पादन का लाभ स्वतः ही आम जनता तक पहुँचेगा और उनका जीवन बेहतर होगा। लेकिन हम ज़मीनी स्तर पर जो देखते हैं, कि असमानताएँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, जहाँ कुछ लोग विलासिता का आनंद ले रहे हैं और आम जनता गरीबी की चपेट में है। शायद, पर्यावरण के बिगड़ते हालात के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। हम देख रहे हैं कि दशकों से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि हो रही है, वैश्विक तापमान अभूतपूर्व रूप से बढ़ रहा है, और लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे समुद्र के आसपास की बस्तियाँ खतरे में हैं, वायु की गुणवत्ता बदतर हो रही है जिससे साँस लेना भी मुश्किल हो रहा है, पानी और मिट्टी अभूतपूर्व रूप से प्रदूषित हो रहे हैं और इस प्रकार पृथ्वी रहने योग्य नहीं बच रही है। भौतिक प्रगति के साथ, मानवता को भौतिक प्रगति प्राप्त करने की लालसा और लालच के रूप में एक और झटका लगा, जिससे सामाजिक और पारिवारिक विघटन हुआ। मूल्यों में यह गिरावट व्यक्तिवाद के उदय के साथ और भी बढ़ गई।

आज, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि को विकास का एक महत्वपूर्ण पैमाना माना जाता है। लेकिन क्या जीडीपी सभी की भलाई और पर्यावरण संरक्षण का प्रतिनिधित्व करती है? शायद नहीं। युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि, वनों की कटाई, बीमारियों की बढ़ती घटनाओं आदि के साथ भी राष्ट्रों की जीडीपी बढ़ सकती है। इसलिए, हम जीडीपी में वृद्धि को अधिक खुशी का पैमाना नहीं मान सकते। यह और भी असंभव है कि जीडीपी में वृद्धि पिरामिड के निचले स्तर पर रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इसके विपरीत, पं. दीनदयाल उपाध्याय विकास का एक वैकल्पिक दर्शन प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम एकात्म मानव दर्शन कहते हैं। वह दर्शन क्या है? उपाध्याय जी का दर्शन कहता है कि सच्चा विकास वह है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुख और सुविधा पहुँचाए, अर्थात अंत्योदय। आर्थिक विकास का लाभ तब तक अधूरा है जब तक वह समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक न पहुँचे। यही विचार आज के सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की नीतियों का भी मार्गदर्शन कर सकता है।

भारत की सांस्कृतिक परंपरा हमेशा से इस विचार पर आधारित रही है कि मनुष्य केवल एक आर्थिक इकाई नहीं है, बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से युक्त एक समग्र इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। इसी गहन समझ के आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन प्रस्तुत किया। यह दर्शन उस समय भी भारत की विकास यात्रा के लिए एक मार्गदर्शक था, और आज, जब वैश्विक आर्थिक असमानता, सामाजिक विखंडन और पर्यावरणीय संकट गहरा रहे हैं, इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। आज की नीतियाँ मुख्यतः भौतिक प्रगति पर आधारित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी प्रगति में भी, लक्ष्य अक्सर "प्रतिस्पर्धात्मक लाभ" और "आर्थिक लाभ" माने जाते हैं। हालाँकि, मनुष्य केवल भौतिक प्राणी नहीं हैं; उसके मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक आयाम भी हैं। यदि विकास शरीर और भौतिक संसाधनों तक सीमित है, तो समाज असंतुलित और तनावग्रस्त हो जाता है। उपाध्याय जी का दर्शन हमें याद दिलाता है कि विकास तभी वास्तविक है जब वह व्यक्ति के इन सभी पहलुओं का संतुलित तरीके से पोषित करे।

सामाजिक और आर्थिक असमानता भारत में लंबे समय से एक चुनौती रही है। जाति, धर्म और वर्ग के विभाजन आज भी समाज को विभाजित करने का प्रयास करते हैं। उपाध्याय समाज को एक "जीवित शरीर" के रूप में देखते हैं, जहाँ प्रत्येक अंग की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है, और कोई भी अंग दूसरे से कम या ज़्यादा नहीं होता। यह दृष्टिकोण समाज में समानता ही नहीं, बल्कि समरसता भी स्थापित करता है, जहाँ सभी को समान सम्मान और महत्व प्राप्त होता है। आज के विखंडित समाज में यह विचार और भी आवश्यक हो गया है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट है। निरंतर औद्योगीकरण और उपभोक्तावाद ने प्रकृति के अत्यधिक दोहन को जन्म दिया है। ऐसे समय में, एकात्म मानव दर्शन हमें बताता है कि मनुष्य और प्रकृति शत्रु नहीं हैं, बल्कि एक सहजीवी संबंध में हैं। जब तक विकास पर्यावरण के अनुकूल और संतुलित नहीं होगा, तब तक वह सतत् नहीं हो सकता। यह दृष्टिकोण आधुनिक सतत् विकास से कहीं अधिक गहरा है क्योंकि यह न केवल संसाधन संरक्षण पर आधारित है, बल्कि प्रकृति को परिवार मानने की भारतीय संस्कृति पर भी आधारित है। वैश्वीकरण के दौर में, आर्थिक नीतियाँ बहुराष्ट्रीय निगमों और बाज़ार की ताकतों के इर्द–गिर्द घूमती हैं। इससे सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक स्वतंत्रता पर ख़तरा बढ़ गया है। एकात्म मानव दर्शन 'भारतीयता', यानी भारतीयता की ओर लौटने का आह्वान करता है। यह कहता है कि नीतियाँ हमारी सांस्कृतिक चेतना और स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित होनी चाहिए। आज, यह दर्शन "आत्मनिर्भर भारत" और "विकसित भारत" जैसे राष्ट्रीय अभियानों में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

जीएसटी में अभूतपूर्व सुधार

2017 में प्रारंभ जीएसटी प्रणाली ने पिछले 8 वर्षों में बड़े उतार–चढ़ाव देखे हैं। लगभग एक दशक की चर्चा और डिबेट के बाद जीएसटी प्रणाली देश में लागू हुई थी। प्रारंभ से ही जीएसटी के बारे में चिंता, शंकाएं और अपेक्षाएं व्यक्त की जाती रही है। जहां प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इसकी आलोचना करती दिखाई देती रही और उनके प्रमुख नेता इसे 'गब्बर सिंह टैक्स' कहते रहे, और प्रारंभ में व्यापारी संगठन इससे जुड़ी कार्यान्वयन की समस्याओं को लेकर इसका विरोध करते दिखाई देते थे; वहीं बड़ी संख्या में अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ इसे एक बड़ा सुधार मान रहे थे।

राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी इस नई कर प्रणाली को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। सरकार ने हालांकि जुलाई 2017 में इस प्रणाली को लागू तो कर दिया था, लेकिन प्रारंभ में इससे पर्याप्त राजस्व प्राप्त करने की प्रमुख चुनौती थी।

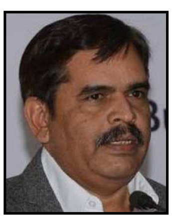

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जीएसटी की दरों में कमी से मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति में भी वृद्धि होगी, जिससे देश में उपभोक्ता माँग ही नहीं, बल्कि निवेश मांग भी बढ़ेगी।

– डॉ. अश्वनी महाजन

क्या है जीएसटी?

जीएसटी यानी 'गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स' एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। जीएसटी से पूर्व देश में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे, जिसमें बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाकर, सीमा शुल्क और कई अन्य कर शामिल थे। इन सभी करों को एकीकृत कर एक ही टैक्स जीएसटी के रूप में लगाया गया। इसका हेतु यह था कि विभिन्न प्रकार के कर लगाने से कर दाताओं और कर एकत्र करते हुए उसे सरकारी राजस्व में जमा करना कठिन होता था और उसको एकत्र करने की लागत भी अधिक आती थी। इसके अलावा विभिन्न करों को लगाने से उसका अनपेक्षित प्रभाव होता था। उदाहरण के लिए अलग–अलग स्तर पर कर लगाने के कारण एक ही वस्तु पर दो और कई बार दो से ज्यादा बार टैक्स देना पड़ता था। इसके कारण सरकार को राजस्व कम प्राप्त होता लेकिन वस्तु की कीमत टैक्स प्राप्ति से कहीं ज्यादा बढ़ जाती थी। इस अनपेक्षित प्रभाव को कैसकेंडिंग प्रभाव कहते हैं।

राजस्व प्राप्ति के स्रोत के रूप में सामान्य तौर पर अप्रत्यक्ष करों को इसलिए सही नहीं माना जाता, क्योंकि इसे अमीर और गरीब सभी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। इसलिए अप्रत्यक्ष करों को प्रगतिशील बनाने के लिए इसे लागू करते हुए विभिन्न वस्तुओं पर अलग–अलग कर लगाना जरूरी माना जाता है। उदाहरण के लिए जीएसटी की 0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिषत की पांच दरें लागू की गई। कृषि उत्पादों समेत कुछ आवश्यक वस्तुओं पर शून्य और अलग–अलग वस्तुओं पर अलग–अलग कर लगाए गए, जिसमें आवश्यक वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया। इसके बाद इसी निष्कर्ष के आधार पर 12, 18 और 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया, जिसमें विलासिता की और हानिकारक वस्तुओं पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाता रहा।

कर दरें ज्यादा हो या कम?

सामान्य तौर पर चाहे किसी भी प्रकार का कर हो – अप्रत्यक्ष कर अथवा प्रत्यक्ष कर, सभी में प्रगतिशीलता लाने हेतु अलग–अलग दर पर कर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए एक स्तर की आय तक शून्य और उसके बाद आय के परिमाण के आधार पर स्लैब बनाकर उन पर बढ़ती दरों पर आयकर लगाया जाता है। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष करों में सामान्य जन अधिकांशतः निम्न आय वर्ग द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर शून्य अथवा बहुत कम कर लगाया जाता है। इसी प्रकार जीएसटी लागू करते समय उसे अधिक प्रगतिशील बनाते हुए उसमें पांच दरें रखी गई थी। उसी समय से इस विषय में अर्थशास्त्रियों के मतभिन्नता देखने को मिलती रही। अर्थशास्त्रियों के एक वर्ग का कहना है कि इसे अधिक कुशल बनाने हेतु एक ही जीएसटी की दर होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था सिंगापुर समेत कई देशों में है। लेकिन वे सभी विकसित देश हैं।

भारत जैसे देश में जहां असमानताएं अधिक विषम है एक ही जीएसटी की दर अपनाना सही नहीं माना जा सकता क्योंकि एक ओर रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं जैसे दूध दही पनीर पैकेज खाद्य पदार्थ साइकिल और दूसरी तरफ़ महंगी कारों पर एक ही जीएसटी की दर को सही नहीं माना जा सकता। इसी कारण जीएसटी को प्रगतिशील बनाने हेतु शून्य सहित पांच दरें रखी गई थी। लेकिन एक विचार जो बार–बार व्यक्त किया जाता रहा कि अधिक दरें होने के कारण असमंजस अधिक होता है, विशेष तौर पर अंतिम वस्तु और अंतिम वस्तुओं की दरें भिन्न होने पर यह असमंजस और भी अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए यह माना गया कि अधिक दरें जीएसटी प्रशासन में एक कुशलता का कारण बनती है। लेकिन जीएसटी में प्रगतिशीलता बनी रहे इसके लिए उसमें शून्य के अतिरिक्त न्यूनतम दो तरह की दरें सही है। ऐसा लगता है कि इसी सिद्धांत पर आधारित 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो दरें रखने का निर्णय हुआ है।

इसके साथ ही साथ यदि सामान्य रूप से विलासिता की वस्तुएं जैसे अत्यधिक महंगी कारें, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुएं जैसे कार्बोरेटेड पेय पदार्थ, सिगरेट, गुटका आदि उत्पादों पर विशेष दर पर जीएसटी लगाया गया है। अनेक उत्पाद जिन पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता था, उन्हें अब शून्य की श्रेणी में लाया गया है। इनमें अधिकांश दुग्ध उत्पादों सहित खाद्य पदार्थ हैं। इसके अतिरिक्त कई उत्पाद जिन पर पूर्व में 12 और 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता था अब 5 प्रतिशत की श्रेणी में आ गए हैं। ऐसे उत्पाद जिन पर पूर्व में 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता था अब 18 प्रतिशत की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। कहा जा सकता है कि जीएसटी की दरों में भारी कमी हुई है। इसी प्रकार जीएसटी की दरों को युक्ति संगत बनाने का भरपूर प्रयास हुआ है।

जीएसटी सुधारो में गिरावट के पीछे की दृष्टि

हालांकि जीएसटी सुधारो से महंगाई में कमी आएगी और इसलिए यह एक लोकप्रिय कदम तो है ही जीएसटी की दरों में कमी और उन्हें युक्ति संगत बनाने के पीछे के उद्देश्यों को समझने की आवश्यकता है।

सर्वप्रथम जीएसटी के दरों में गिरावट ऐसे समय पर आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के अधिकांश उत्पादों पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण और उसमें स्वदेशी के आग्रह को भी उसके साथ जोड़कर देखा जा सकता है। जीएसटी दरों में कमी से देश में बने उत्पाद अब पहले से सस्ते हो जाएंगे, जिससे स्वदेशी उत्पादों का उपभोग तो बढ़ेगा ही साथ ही साथ हमारे उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे।

दूसरे जीएसटी दरों में कमी से सामान्य उपभोग की वस्तुएं पहले से सस्ती होगी इससे मुद्रास्फीति में कमी होगी। मुद्रास्फीति में कमी का सकारात्मक प्रभाव आर्थिक ग्रोथ पर पड़ता है। मुद्रास्फीति में कमी से ब्याज दरों में कमी आती है जिससे निवेश बढ़ता है। इससे हाउसिंग क्षेत्र और स्थाई वस्तुओं का उपभोग बढ़ाने में मदद मिलती है।

तीसरी जीएसटी दरों में कमी से नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र को राहत और प्रोत्साहन देने का प्रयास हुआ है। सोलर और पवन ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। अपेक्षा की जा सकती है कि अब नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही, नवीनीकरण ऊर्जा की लागत भी घटेगी, जिससे अब भारत इस क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा।

चौथे कृषि उपकरणों और इनपुट पर जीएसटी में कमी से कृषि की लागत कम होगी। लागत घटने से किसानों की हालत में सुधार तो होगा ही हमारे कृषि उत्पादन वैश्विक दृष्टि से अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे।

पांचवें, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जीएसटी की दरों में कमी से मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति में भी वृद्धि होगी, जिससे देश में उपभोक्ता माँग ही नहीं, बल्कि निवेश माँग भी बढ़ेगी।❑❑

सुधार से आसान होती विकसित अर्थव्यवस्था की राह

आजकल सोशल मीडिया पर एक मीम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नई गाड़ी और नए घर वाले सुनील बाबू जीएसटी की कटौती दर को लेकर खासे पेशोपेश में है। वह बहुत–बहुत खुश है तो कुछ–कुछ उदास भी हैं। उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर कम होने के कारण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत घट जाने से बचत के बढ़ने की उम्मीद पाल रखी है लेकिन उनकी श्रीमती जी ने घटे हुए दामों का हवाला देकर खरीदारी की फेहरिश्त पहले की तुलना में और लंबी कर दी है। मीम में सुनील बाबू खर्च और बचत का तुलनात्मक हिसाब किताब लगाते हुए दिखते हैं। विज्ञापन में सुनील बाबू अपने मासिक आय–व्यय को लेकर भले थोड़ी देर के लिए ठहर गए हैं लेकिन जीएसटी कर सुधार की घोषणा के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होना लाजमी है। त्यौहारी सीजन के दौरान बाजार के खिलखिलाने की आहट अभी से आने लगी है।

जीएसटी सुधार केवल कर संग्रहण की प्रक्रिया नहीं है बल्कि आर्थिक ढांचे को दीर्घकालिक मजबूती देने वाली रणनीति है। मसाला कराधान को जटिलता या पारदर्शिता भर का नहीं, बल्कि इस बात से जुड़ा है कि भारत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में किस तरह स्थापित करता है यहीं से यह सुधार एक कर नीति से आगे बढ़कर विकास का रूप लेता हैं। नए सुधारों का लक्ष्य कर आधार को विस्तारित करना, दरों को सरल बनाना और रिसाव को रोकना है। किंतु जब तक इन प्रावधानों को व्यावहारिक स्तर पर लागू नहीं किया जाएगा परिणाम सीमित ही रहेंगे, कर भुगतान की पूरी डिजिटल व्यवस्था छोटे उद्योगों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोगी इन सुधारो की सफलता तय करेंगे।

केंद्र और राज्यों को मिलकर ऐसी नीति बनानी होगी जहां एमएसएमई को सस्ता ऋण आसान, बाजार पहुंच और कौशल विकास की वास्तविक सुविधा मिले तभी जीएसटी सुधार भारत को कराधान की जटिलताओं से मुक्त कर आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी, अर्थव्यवस्था के साथ–साथ 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

–अनिल तिवारी

अति आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की दर घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया जाना और कई जीवन रक्षक दवाइयों पर कर दर शून्य प्रतिशत होना केवल कर सुधार नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण को और अधिक गति देने का परिचायक है। जिस तरह भारतीय बाजार में मांग बढ़ रही है, उससे लगने लगा है कि यह न सिर्फ समर्थ भारत के सपनों को पंख लगाने वाला निर्णय है बल्कि दुनिया के नक्शे पर भारत की सकारात्मक को प्रदर्शित करने वाली पहल है।

जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी है। लगभग 400 आइटम पर टैक्स कम हो गया है। सरकार ने जीएसटी में पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत के अलावा बाकी सभी स्लैब को खत्म कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने पुराने जटिल कर ढांचे को सरल बनाते हुए नागरिकों के अनुकूल दो स्लैब संरचना में चीजों को समाहित कर दिया है। इसके तहत आवश्यक वस्तुओं पर पांच प्रतिशत और सामान्य वस्तुओं और सेवाओं पर 18 प्रतिशत का कर निर्धारण किया गया है, वही विलासिता एवं हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत तक का टैक्स लगाया गया है। वर्ष 2017 में देश में लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर का उद्देश्य देश की कर प्रणाली में बदलाव लाना था, जिसके तहत करों के जटिल जाल को एकीकृत कर प्रणाली से बदला गया। हालांकि इसके प्रभाव को दोधारी तलवार की संज्ञा देते हुए पक्ष और विपक्ष द्वारा इसके फायदे और नुकसान गिनाए जाते रहे। इस बीच 3 सितंबर 2025 को 56 वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कर सुधारों की घोषणा हुई, जो कि गत 22 सितंबर

से पूरे देश में लागू है। प्राथमिक रुझानों को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह न सिर्फ सरकार का एक साहसिक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है बल्कि भारत की आर्थिक क्रांति को मजबूती देते हुए एक बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने का जरिया भी है।

लागू टैक्स स्लैब से दैनिक आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध चावल आटा चाय दही किताब रोटी अब या तो कर मुक्त है या उस पर सिर्फ पांच प्रतिशत कर लग रहा है। यह केंद्र की सरकार की गरीब और मध्यम वर्ग के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है ताकि कोई भी भारतीय परिवार अपनी रोजमर्रा की जरूरत से अत्यधिक बोझिल ना हो। यह सरकार के 'सबका साथ–सबका विकास–सबका विश्वास' की प्रतिबद्धता का भी परिचायक है।

इस कड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन बीमा पॉलिसीयां कर मुक्त कर दी गई है, वही जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी घटाकर शून्य कर दिया गया है। सरकार ने आम आदमी के दुख दर्द के प्रति अपनी संवेदना दिखाई है तथा संकट की घड़ी में गरिमा और राहत के लिए हर संभव मदद का संदेश दिया है। इसी तरह कृषि प्रधान भारत देश की रीढ़ समझे जाने वाले किसानों के लिए भी ट्रैक्टर सिंचाई प्रणाली खाद और कीटनाशकों पर जीएसटी घटकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे खेती की लागत घटेगी और ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि होगी। महिलाओं, युवाओं और छोटे तथा मझौले उद्यम के लिए भी राहत की घोषणा की गई है। मौजूदा सुधार से कपड़ा और उर्वरक उद्योग जो लंबे समय से उल्टे कर ढांचे से जूझ रहे थे को लाभ मिलेगा। वहीं सरकार की इस पहल से मध्यम वर्ग का भी सशक्तिकरण होगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने जीएसटी अपील न्यायाधिकरण शुरू करने की घोषणा की है जो कि दिसंबर 2025 तक अपना काम शुरू कर देगी इसके लिए सरकार के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है की बरसों से आ रही परेशानियों को दूर करते हुए व्यवसाय में पारदर्शिता तथा न्याय के साथ शीघ्र समाधान का रास्ता तैयार किया जा सके। 'नारी शक्ति भारत की प्रगति की चालक है' जैसी सोच के साथ महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए सरल जीएसटी और आसान क्रेडिट पहुंच से महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को विस्तार रोजगार और नवाचार के नए–नए अवसर उपलब्ध कराने के भी संकेत प्राप्त हुए हैं।

सरकार ने नवरात्रि से दीपावली तक जीएसटी सुधारों तथा इससे होने वाले लाभों को समझने के लिए सांसदों को अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यापारियों के साथ संवाद करने का भी खाका तैयार किया है। ऐसी बैठकों में रजक सांसदों से भारत में बने उत्पादों को बढ़ावा देने तथा जीएसटी दरों में कटौती किए जाने के बाद व्यापारिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए भी रणनीति बनाने की बात कही गई है। जीएसटी 2.0 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा कि 'यह राष्ट्र के लिए समर्थन और वृद्धि की दोहरी खुराक है, जो 21वीं सदी के भारत की प्रगति को ध्यान में रखकर अगली पीढ़ी के लिए सुधारात्मक उपाय की तरह प्रस्तुत है'।

मालूम हो कि जीएसटी में व्यापक सुधार रातों–रात नहीं हुआ बल्कि इसकी शुरुआत माल एवं सेवा कर परिषद की पिछले साल दिसंबर में जैसलमेर में हुई बैठक से पहले ही हो गई थी। इसके लिए एक मंत्री समूह पिछले डेढ़ साल से कम कर रहा था। बैठकों में इस बात की गहन समीक्षा की गई की न केवल कर स्लैब कम किए जाएं बल्कि लघु और मझौले व्यवसाय के लिए यह कैसे अति उत्तम हो सकता है उस पर गहनता से काम किया गया।

दशकों तक भारतीय आर्थिक विकास की गति सुस्त रही। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद विकास ने गति पकड़ी। बाद में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नेतृत्व वाले उदारीकरण ने इस गति को और बढ़ाया। बीच में राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद, राष्ट्र ने 1991 के बाद, पिछले पांच दशकों की तुलना में दोगुनी दर से वृद्धि की। ये सुधार मुख्य रूप से व्यापार और बाहरी क्षेत्र पर केंद्रित थे। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा तो बढ़ी लेकिन आंतरिक सुधारों के आभाव के कारण औद्योगिक विस्तार रूका और केवल सर्विस सेक्टर बढ़ा। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में मैन्यूफैक्चरिंग का योगदान लगातार 15–16 प्रतिशत के आसपास ही बना रहा है जबकि सर्विसेज सेक्टर 38 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक पहुंच गया। पर्याप्त संख्या में अच्छी तनख्वाह वाली मैन्यूफैक्चरिंग में नौकरियों की कमी तब से एक स्थायी चुनौती रही है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का अनुभव भी इन दावों की पुष्टि करता है। भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर्निहित बाधाएं उद्यमियों को उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकती हैं। 6.4 करोड़ उद्यमों में 99 प्रतिशत सूक्ष्म बने रहते हैं और बमुश्किल एक प्रतिशत छोटे हैं जबकि मध्यम उद्यमों का आकार इतना छोटा है कि यह 0.5 प्रतिशत से कम है। 140 करोड़ के राष्ट्र में 30 लाख से अधिक औद्योगिक बिजली कनेक्शन नहीं हैं और 10 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली फैक्ट्रियों की संख्या बमुश्किल 2.5 लाख है। इसका नतीजा बहुत छोटे पैमाने के उद्योग, अनौपचारिक रोजगार और

(शेष पृष्ठ 13 पर ...)

भारत का विदेशी व्यापार और आत्मनिर्भरता

अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने विदेशी व्यापार को नया आयाम दिया है। दूसरे महायुद्ध के बाद विदेशी व्यापार को एक मुक्त व्यापार की ओर जोर जबरदस्ती ले जाने वाला अमरिका अब संरक्षणात्मक व्यापार पर जोर दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह सहूलियत वह दूसरे देशों को देने को तैयार नहीं है। यहाँ भी जोर–जबरदस्ती की बात हो रही है। भारत को तो धमकियां दर धमकियां मिल रही है। इसलिये वैश्विक व्यापार आज अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और अमेरिका तथा यूरोप के संरक्षणवाद से भारत जैसे विकासशील देश सकते में आ गये है। वैसे भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का हिस्सा बढ़ता जा रहा है और सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। भारत की अपनी संरचना विदेशी व्यापार में लचीलापन रखती है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, वैसे ही उसमें विदेशी व्यापार का महत्व बढ़ रहा है। आयात तेज़ी में है और उसके मुकाबले निर्यात की गति अपेक्षाकृत कम है। और तो और विदेशी व्यापार में घाटा भी बढ रहा है, इन्हीं कारणों से आत्मनिर्भरता की ज़रूरत महसूस होती है।

विदेशी व्यापार संकल्पना

वैसे कोई व्यक्ति, समाज या देश पूर्णतः सक्षम नहीं होता। किसी न किसी बात पर उसे दूसरे की जरूरत रहती है। इसलिए यह बात चर्चा का विषय नहीं है कि विदेश व्यापार होना चाहिए या नहीं। विदेश व्यापार अर्थव्यवस्था का अंगभूत क्षेत्र होता है और वैसे ही उसे देखना और समझना चाहिए। जब तक दुनिया में अलग–अलग देश है और पर्यावरण की दृष्टि से भी उनकी अलग–अलग विशेषताएँ तथा क्षमता है, तब तक विदेशों से व्यवहार भी होता रहेगा और व्यापार भी, और वह एक दूसरे को लाभदायक भी है। अपनी–अपनी विशेषताओं से भरा वस्तु तथा सेवाओं का आदान–प्रदान होना मानव जाति के हित में ही है। सवाल यह है कि यह व्यवहार और व्यापार किन शर्तो के आधार पर होगा और इसमें होने वाले फायदे–नुकसान को कैसे सुलझाया जाएगा। जरूरी है कि इसमें सभी देशों की अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए और किसी पर भी अंतरराष्ट्रीय दबाव में व्यापार की मजबूरी न हो। अपनी विशेष क्षमता का उपयोग कर एक दूसरे की ज़रूरते पूरी हो, यही व्यवहार व्यापार को सफल बनाएगा। विदेशी

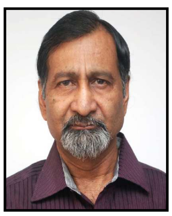

भारत को विदेशी व्यापार में ऐसी नीति अपनानी होगी जो एक ओर उच्च मूल्यवर्धित निर्यात से आर्थिक शक्ति बढ़ाए, और दूसरी ओर आवश्यक आयात को स्थायी एवं संतुलित ढंग से संचालित करे। इस प्रकार विदेशी व्यापार, आत्मनिर्भर भारत और मानव–केन्द्रित विकास की परिकल्पना का वास्तविक साधन बन सकता है।

–अनिल जवलेकर

व्यापार स्थानीय जीवन को समृद्ध करे, यही हर देश की नीति होनी चाहिए। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद हमें स्मरण कराता है कि नीति केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने का साधन नहीं होनी चाहिए, बल्कि मनुष्य, समाज और संस्कृति के उत्थान का माध्यम होनी चाहिए। इस दृष्टि से विदेश व्यापार या आयात–निर्यात नीति केवल फायदे–नुकसान का उपकरण नहीं, बल्कि स्थानीय समाज को वैश्विक अवसर से जोड़ने का साधन है।

भारतीय विदेश व्यापार की स्थिति

भारत का विदेशी व्यापार इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है – प्राचीन काल में भारत मसाले, वस्त्र और धातु–शिल्प के निर्यात से विश्व का "कारख़ाना" माना जाता था और व्यापार अधिशेष अर्जित करता था। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन ने इसे कच्चे माल के निर्यातक और तैयार वस्तुओं के आयातक में बदल दिया, जिससे पारंपरिक उद्योग नष्ट हुए और व्यापार घाटा बढ़ा। स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1991 तक भारत ने आत्मनिर्भरता और आयात–प्रतिस्थापन की नीति अपनाई, जहाँ निर्यात सीमित और आयात नियंत्रण में रहा। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उदारीकरण, वैश्वीकरण और सेवा–क्षेत्र (विशेषकर आईटी) ने भारत के विदेशी व्यापार को नई दिशा दी। आज भारत ऊर्जा व सोने के आयात पर निर्भर होने के बावजूद विविधीकृत निर्यात (फार्मा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेवाएँ) के साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में जगह बनाने का प्रयास कर रहा है, और 2030 तक निर्यात में महत्त्वपूर्ण वृद्धि का लक्ष्य रखता है।

आज भारत का विदेशी व्यापार लगभग यूएस +820 अरब निर्यात और यूएस +915 अरब आयात (वित्तीय वर्ष 2024–25) तक पहुँच चुका है, जिससे करीब यूएस +94 अरब का व्यापार घाटा बनता है। निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, इंजीनियरिंग, सेवाएँ और कृषि–उत्पाद प्रमुख हैं, जबकि आयात में पेट्रोलियम, सोना, मशीनरी व इलेक्ट्रॉनिक घटक मुख्य हैं। भारत का व्यापार धीरे–धीरे विविधीकृत हो रहा है, पर ऊर्जा और कच्चे माल पर आयात–निर्भरता अभी भी बड़ी चुनौती है। प्रमुख साझेदारों में चीन (15 प्रतिशत आयात), अमेरिका (भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य), यूएई (तेल व सोना), और रूस (ऊर्जा) शामिल हैं। इन देशों के साथ व्यापार का स्वरूप अलग–अलग है – जहाँ अमेरिका व यूरोप को उच्च मूल्य वर्धित उत्पाद और सेवाएँ भेजे जाते हैं, वहीं चीन व रूस से भारत को बड़े पैमाने पर ऊर्जा, कच्चा माल और विनिर्माण सामग्री मिलती है। इस प्रकार भारत का विदेशी व्यापार अवसर और निर्भरता, दोनों का मिश्रण है।

भारतीय विदेशी व्यापार का लचीलापन और नीति की गुंजाईश

भारतीय विदेशी व्यापार में लचीलापन स्पष्ट रूप से दिखता है – जब वैश्विक मांग बढ़ती है तो भारतीय निर्यात, विशेषकर आईटी सेवाएँ, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग वस्तुएँ, तेजी से प्रतिसाद देते हैं; वहीं कच्चे तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे आयात मूल्य में थोड़े उतार–चढ़ाव भी भारत के आयात बिल को भारी रूप से प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ है कि भारत के निर्यात अपेक्षाकृत मांग–लचीले हैं, जबकि आयात, खासकर ऊर्जा, अधिक अनिवार्य और कम लचीले रहते हैं। इसलिए भारत को ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा, नवीकरणीय स्रोत और दीर्घकालीन आयात समझौतों पर जोर देना होगा। साथ ही, निर्यात की विविधता बढ़ाने, उच्च मूल्य–वर्धित उत्पादन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से गहरे जुड़ाव के लिए पीएलआई योजनाएँ, आरओडीटीईपी और एफटीए समझौते महत्वपूर्ण औजार हैं। इससे भारत का विदेशी व्यापार अधिक संतुलित, टिकाऊ और वैश्विक झटकों के प्रति लचीला बनाया जा सकता है।

भारतीय विदेशी व्यापार और आत्मनिर्भरता नीति

भारतीय विदेशी व्यापार को यदि एकात्म मानववाद के दृष्टिकोण से देखें तो यह केवल आयात–निर्यात संतुलन या विदेशी मुद्रा अर्जन का विषय नहीं रह जाता, बल्कि मानव–केन्द्रित, समाज–हितैषी और संतुलित विकास का माध्यम बन जाता है। पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचारानुसार आर्थिक नीति का उद्देश्य मात्र उत्पादन–वृद्धि नहीं बल्कि समान्य जन की आवश्यकताओं की पूर्ति, सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भरता है। इस संदर्भ में विदेशी व्यापार का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि वह देश की मूलभूत जरूरतों को पूरा करे, घरेलू उद्योग और कृषि को प्रोत्साहित करे तथा आयात–निर्भरता को न्यूनतम करे।

आज भारत का निर्यात विविधीकृत हो रहा है – सेवाएँ, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि प्रसंस्कृत उत्पाद वैश्विक बाजार में मजबूत स्थान बना रहे हैं, परंतु आयात, विशेषकर ऊर्जा और सोने पर अत्यधिक निर्भरता, हमारी आर्थिक असुरक्षा को बढ़ाती है। एकात्म मानववाद का मार्गदर्शन बताता है कि व्यापार नीति को केवल वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर आधारित न रखकर, "आवश्यकताओं की पूर्ति + स्वदेशी उत्पादन क्षमता + समाजोन्मुख संतुलन" पर केंद्रित होना चाहिए। इसका अर्थ है कि भारत को विदेशी व्यापार में ऐसी नीति अपनानी होगी जो एक ओर उच्च मूल्यवर्धित निर्यात से आर्थिक शक्ति बढ़ाए, और दूसरी ओर आवश्यक आयात को स्थायी एवं संतुलित ढंग से संचालित करे। इस प्रकार विदेशी व्यापार, आत्मनिर्भर भारत और मानव–केन्द्रित विकास की परिकल्पना का वास्तविक साधन बन सकता है।❑❑

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढते कदम

आज की दुनिया तकनीकी क्रांति के दौर से गुजर रही है। जिस प्रकार 19वीं और 20वीं शताब्दी में कोयला और तेल वैश्विक औद्योगिक विकास के केंद्र में थे, उसी प्रकार 21वीं शताब्दी में सेमीकंडक्टर तकनीकी प्रगति की रीढ़ बन चुके हैं। इनकी बदौलत ही आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, ऑटोमोबाइल, रक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव संभव हो पा रहे हैं। यही कारण है कि सेमीकंडक्टर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों का केंद्रीय विषय बन चुका है।

सेमीकंडक्टर हर डिजिटल डिवाइस का हृदय होते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स मोबाइल, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, रक्षा, स्वास्थ्य उपकरण, 5जी नेटवर्क, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष तकनीक जैसे लगभग हर क्षेत्र में अनिवार्य हैं। इसे 21वीं सदी का 'तेल' भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह तेल ने औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाया, उसी तरह सेमीकंडक्टर डिजिटल और तकनीकी क्रांति को गति दे रहे हैं।

भारत 'मेक इन इंडिया' के तहत अपने औद्योगिक विकास को गति देने का प्रयास कर रहा है। 2047 तक भारत को विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है तो ऐसे में अगर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में दुसरे देशो पर निर्भरता रही तो रणनीतिक रूप से यह सही नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखकर और भविष्य की आवश्यकताओं की रूपरेखा के तहत भारत ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए "इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन" को गति प्रदान की है। पिछले दिनों 'सेमिकॉन इंडिया 2025' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में निर्मित 'विक्रम' 32–बिट लॉन्च व्हीकल ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर भेंट किया गया, जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। विक्रम 3201 का प्रारंभिक अंतरिक्ष परीक्षण पीएसएलवी सी–60 मिशन के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि यह माइक्रोप्रोसेसर भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिये विश्वसनीय है।

भविष्य में जो देश सेमीकंडक्टर तकनीक और व्यापार पर नियंत्रण रखेगा, वही दुनिया की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और तकनीकी नेतृत्व को निर्धारित करेगा। इसलिए यह कहना उचित होगा कि सेमीकंडक्टर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आने वाले दशकों में निर्णायक साबित होगा।

– दुलीचंद कालीरमन

विक्रम 3201 को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल), चंडीगढ़ द्वारा विकसित किया गया है। यह 16–बिट विक्रम–1601 का ही उन्नत संस्करण है, जिसका उपयोग वर्ष 2009 से इसरो प्रक्षेपण यानों में किया जा रहा था। इसे अंतरिक्ष उड़ान अनुप्रयोगों के लिये डिज़ाइन किया गया है, जो –55 सेंटीग्रेट से 125 सेंटीग्रेट तक के चरम तापमान को सहन करने में सक्षम है जो इसरो के लॉन्च व्हीकल्स के नेविगेशन, गाइडेंस और नियंत्रण प्रणालियों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करता है।

भारत में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण को लेकर पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इसे लेकर सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर "इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन" चला रहे हैं। भारत का लक्ष्य 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत भारत स्वयं सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण करना चाहता है। अभी तक भारत ज्यादातर चिप्स ताइवान, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से आयात करता है। भारत का चिप आयात लगभग 20–25 अरब डॉलर का है। 2021 में भारत सरकार ने रू. 76,000 करोड़ की सेमिकॉन इंडिया स्कीम शुरू की। जिसका मुख्य उदेश्य भारत में चिप फैब्रिकेशन यूनिट्स लगाना एवं चिप डिज़ाइन के

क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है।

सेमीकंडक्टर चिप निर्माण वास्तव में बहुत जटिल तकनीकी कौशल और बड़े निवेश का विषय है। वेदांता और फोक्सकॉन मिलकर गुजरात में चिप फेब्रिकेशन यूनिट लगाने की योजना पर काम कर रहें है। इसके अलावा गुजरात के सानंद में अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी अपनी यूनिट बना रहा है। नेक्स्ट ऑर्बिट और टावर सेमीकंडक्टर संयुक्त रूप से कर्नाटक में फैब यूनिट की योजना पर काम कर रहे है। टाटा टेक्नोलॉजी चिप पैकेजिंग और डिज़ाइन में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के जेवर में भी एचसीएल–फोक्सकॉन की वफ़र फेब्रिकेशन यूनिट का कार्य प्रगति पर हैं। भारत पहले से ही चिप डिजाईन के हब के रूप में कार्य कर रहा है। चिप डिजाईन के क्षेत्र में लगभग 20 प्रतिशत से अधिक इंजीनियर भारतीय हैं। इंटेल, कुआलकॉम, मीडिया टेक, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, एनविडिया जैसी कंपनियों के अनुसंधान और विकास केंद्र भारत में हैं।

भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर चिप आपूर्ति शृंखला में बड़ी भूमिका निभाने का मौका है। 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि वह 300 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन करे, जिसमें से चिप्स महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। भारत धीरे–धीरे चिप डिज़ाइन से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है।

भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग अभी एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है – सरकार द्वारा प्रोत्साहन, निवेश, मांग, कौशल विकास आदि के कारण इस क्षेत्र में काफी नए अवसर हैं। भारत में बढते औद्योगिकीकरण से सेमीकंडक्टर उपयोग की मांग 2025 से 2030 के बीच लगभग 15 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। अभी सेमीकंडक्टर से सम्बंधित बाजार का आकार लगभग 45–50 अरब डॉलर है जो 2030 तक बढ़कर 100–110 अरब डॉलर तक बीच पहुँच सकता है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डेटा सेंटर्स इत्यादि क्षेत्रों में वृद्धि इलेक्ट्रिक वाहनों, 5जी/6जी नेटवर्क, नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर, कृत्रिम बुधि व डेटा सेंटर्स की मांग बढ़ेगी; ये सब सेमीकंडक्टर की जरूरत को और बढ़ाएँगे। क्योंकि भारत इन क्षेत्रों में तेजी से निवेश कर रहा है।

भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) शुरू की है, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन, निवेश की मंजूरी, टैक्स और सब्सिडी आदि शामिल हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ (पीएलआई) और राज्य सरकारों की नीतियाँ प्रोत्साहन की ज़मीन तैयार कर रही हैं। जिससे बड़े वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माता और बहुराष्ट्रीय कंपनिया भारत में अपने यूनिट्स लगाना चाह रही हैं। इस मिशन का लक्ष्य यह है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए और निर्यातक बने।

भविष्य में जो देश सेमीकंडक्टर तकनीक और व्यापार पर नियंत्रण रखेगा, वही दुनिया की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और तकनीकी नेतृत्व को निर्धारित करेगा। इसलिए यह कहना उचित होगा कि सेमीकंडक्टर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आने वाले दशकों में निर्णायक साबित होगा। यदि भारत समय रहते तकनीकी विशेषज्ञता और निवेश आकर्षित कर पाए, तो वह वैश्विक व्यापार का बड़ा केंद्र बन सकता है। ❑❑

(पृष्ठ 9 का शेष...)

सुधार से आसान होती विकसित अर्थव्यवस्था ...

वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में असमर्थता के रूप में हमारे सामने है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की दृष्टि में मजबूत और टिकाऊ औद्योगिक विकास प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की एक नई लहर शुरू करने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि कर सुधार के साथ–साथ आर्थिक विकास को मूल में रख कर, शहरों की प्रशासनिक व्यवस्था, विकास और मास्टर प्लान डिजाइन पर पुनर्विचार किया जाए।

एमएसएमई महत्वपूर्ण उत्पाद श्रेणियों/उप–क्षेत्रों में तकनीकी कमियों की पहचान करने और इस कमी को स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के माध्यम से या विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करके पूरा करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन की आवश्यकता है। यह मिशन चरणबद्ध तरीके से अध्ययन कर सकता है कि सबसे अधिक संकटग्रस्त उत्पादों को कैसे प्राथमिकता दी जा सकती है?

कुल मिलाकर समाधान यही है कि सुधार को केवल राहत–सुधार की दृष्टि से ना देखा जाए बल्कि उसे रोजगार, उद्यमिता और नवाचार का आधार बनाया जाए। केंद्र और राज्यों को मिलकर ऐसी नीति बनानी होगी जहां एमएसएमई को सस्ता ऋण आसान, बाजार पहुंच और कौशल विकास की वास्तविक सुविधा मिले तभी जीएसटी सुधार भारत को कराधान की जटिलताओं से मुक्त कर आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी, अर्थव्यवस्था के साथ–साथ 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। ❑❑

आपदाओं से त्रस्त उत्तराखंड

इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व वर्ष 2013 में गढ़वाल के चार धामों में केदारनाथ में सबसे भयानक आपदा का स्मरण करना आवश्यक जिसमे हज़ारों श्रद्धालु मृत्यु को प्राप्त हुए और उनके अवशेष तक नहीं मिले। केदारनाथ मंदिर को छोड़कर सम्पूर्ण नगर नष्ट हो गया और कुछ नहीं बचा। उनकी आत्मा को शांति की प्रार्थना के साथ अपने ह्रदय के उद्‌गार व्यक्त किए हैं।

भू–स्लखन और पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के चर्चा करें तो वर्ष 2023 में जोशीमठ में पूरे नगर में सैंकड़ों मकानों और सड़कों में दरारें आ गयीं जिससे बड़ी संख्या में लोगों को जोशीमठ से विस्थापित होना पड़ा। वर्ष 2016 में पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनीस्यारी में भारी भू–स्खलन हुआ और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। वर्ष के 2018 में उत्तरकाशी में भटवाड़ी और यमुनोत्री में भू–स्लखन में भारी तबाही हुई। वर्ष 2019 में रुद्रप्रयाग में बहुगुणा नगर में दर्जनों घरों में दरारें आ गईं और उनको असुरक्षित घोषित कर दिया गया। वर्ष 2021 में चमोली के रैणी और तपोवन क्षेत्र में भू–स्लखन और धंसाव की बड़ी घटनाएं रिकॉर्ड की गयीं। वर्ष 2022 में ग्वालदम और थराली (चमोली) में बड़े स्तर पर धंसाव और भू–स्लखन के कारण बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा।

उत्तराखण्ड विश्व के सबसे सुन्दर, रमणीक, प्राकृतिक भव्य और समृद्ध, हिंदू धर्म और संस्कृति को सहेजे एक अद्वितीय स्थान है जहाँ सम्पूर्ण भारत और विश्व के विभिन्न देशों से आए पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस देवभूमि के निवासी भी इस देवलोक के धार्मिक संस्कृति और परंपराओं को आत्मसात करते इसके सौंदर्य को और भी सुंदर बनाते हैं। एक पर्यटक के रूप में इस देवभूमि के पवित्रता और सौंदर्य को समझना कठिन है और एक श्रद्धालु के लिए एक जीवन इस देवलोक को समझने के लिए कम है। जो उत्तराखंड के निवासी कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने पगडंडियों से हाईवे तक की जीवन यात्रा देखी और अपने कुलदेवताओं में अपना अस्तित्व देखा है। अपने जीवन के कुछ बहुमूल्य वर्ष भी यदि इस देवभूमि में बिताए हैं तो वह कालखंड इस जीवन के सबसे बहुमूल्य वर्ष स्मरण रहता है।

टिहरी, आसपास के कस्बों और गांवों के लिए एक बड़ी मंडी था और फलता फूलता सुंदर नगर था और मेरे ही सामने उसको उजाड़ दिया और मेरे ही सामने वह जलमग्न हो गया।

इस वर्ष ऋतु में उत्तराखंड से बार बार भू–स्लखन, सैकड़ों लोगों की अकाल मृत्यु, हज़ारों मवेशियों का बह जाना, बड़ी संख्या में घरों का भूमि में समा जाना, पूरा पूरा शहर नष्ट होना, कितना ह्रदय विदारक है। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में यह विनाशलीला सीमित रूप से ही प्रकाशित होती है इसलिए उत्तराखंड के स्थानीय समाचार पत्रों और सूचनाओं को संकलित करने का प्रयास किया। यह सत्य है कि उत्तराखंड की प्रदेश सरकार, केंद्रीय सरकार और आपदा प्रबंधन सजगता से पीड़ितों को मानवीय सहायता पहुंचा रहे है और लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार तत्परता से उत्तराखंड में अतिवृष्टि से होने वाले नुकसान का आंकलन कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा पीड़ित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। परंतु विनाशलीला इससे कहीं भयानक है और छोटे–छोटे गांवों की अनगिनत सड़कें कट गयीं है जहाँ आपदा प्रबन्धन असंभव हो रहा है और मानवीय सहायता, राशन आदि पहुँचना भी सम्भव नहीं है।

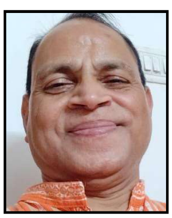

इस वर्ष अगस्त 2025 में उत्तरकाशी में अत्यधिक वर्षा के कारण जो पहाड़ खिसकने, बाढ़ आने, पहाड़ों का मलबा गिरने, नदियों के उफान में गांव के गांव नष्ट होने का जो क्रम प्रारंभ हुआ वह समाप्त नहीं हो रहा।

–**विनोद जौहरी**

उत्तराखंड आर्थिक दृष्टि से मूलतः कृषि प्रधान प्रदेश है जहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि ही मुख्य आय सृजन का साधन है। इतनी अधिक वर्षा, बाढ़ और भू–स्लखन में जनजीवन के हानि के साथ कृषि और पशुधन का भी बहुत नाश हुआ है। इस बार के वर्षा ने स्थानीय सूत्रों के अनुसार पिछले 74 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। सितंबर माह में औसत 167.50 मिलीमीटर से 109 प्रतिशत अधिक वर्षा का अनुमान है और इससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। संकट अभी टला नहीं है।

हमारे वेद पुराणों में पर्यावरण की रक्षा, उसके साथ सामंजस्य और प्रकृति के नियम पालन करने के लिए सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध है। फिर देवभूमि में ही क्यों प्रकृति की विनाशलीला हुई? उत्तराखंड की इस विनाशलीला को क्या कहें? प्रकृति का आक्रोश या जलवायु परिवर्तन या विशालकाय परियोजनाएँ, प्रकृति का दोहन या अनियमित शहरीकरण, धार्मिक स्थलों का अति व्यवसायीकरण या सारे उत्तराखंड में नदियों और झरनों के किनारे नदियों के भूमि पर अतिक्रमण करके होटल, जंगलों की कटाई, रिसोर्ट और शहर बसाने का पाप या यह सभी कारण एक साथ। पर्वतीय क्षेत्रों में जंगलों की कटाई भी बहुत प्रमुख कारण है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में केवल विकास योजनाओं और अनियमित विकास के क्षेत्रों में भू स्लखन, धँसाव और दरारों के घटनाएँ हुई हैं बल्कि निर्जन क्षेत्रों में भी भू स्लखन की घटनाएँ हुई हैं।

डी.बी.एस. कॉलेज देहरादून के प्रख्यात भूगर्भ शास्त्री एवं पूर्व विभागाध्यक्ष भूगर्भ विज्ञान श्री एम एन जोशी का मानना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अनियमित विकास विनाशलीला का प्रमुख कारण है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए अध्ययन से ज्ञात होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जंगलों की कटाई से प्रति वर्ष 28000 लोगों की अकाल मृत्यु होती है।

आपदाओं की चर्चा करें तो अभी हाल में उत्तरकाशी कें सिलक्यारा में सुरंग परियोजना में दुर्घटना हुई थी। 12 नवंबर 2023 को सुबह पांच बजे सिलक्यारा सुरंग में हादसा हो गया कि उत्तरकाशी की ध्वस्त सिलक्यारा–बड़कोट सुरंग में पिछले सप्ताह से फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए चल रहे ऑपरेशन में 17 दिन बाद सफलता हासिल हो पाई। सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लगातार पांच मोर्चों पर काम चल रहा था। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने मशीनों के लिए पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए एक पहुंच मार्ग बनाया, जहां से एक लाइफ लाइन पाइप ड्रिल किया गया था।

इस वर्ष अगस्त 2025 में उत्तरकाशी में अत्यधिक वर्षा के कारण जो पहाड़ खिसकने, बाढ़ आने, पहाड़ों का मलबा गिरने, नदियों के उफान में गांव के गांव नष्ट होने का जो क्रम प्रारंभ हुआ वह समाप्त नहीं हो रहा। इसके अतिरिक्त सरकारी परियोजनाओं में भी भारी नुकसान हुआ और विद्युत परियोजनाओं में बड़े व्यवधान खड़े हुए। एक समय सात विद्युत परियोजनाओं में से सात ढकरानी, रामगंगा, छिबरो, खोदरी, ढालीपुर, चीला और ब्यासी में बिजली उत्पादन ठप्प हो गया था जिसके कारण 13 पॉवर हाउस केवल 63 मेगावाट की क्षमता पर चल रहे थे। बहुत कठिनाई से बिजली उत्पादन प्रारंभ हो सका। कुल्हाल, मोहम्मदपुर, तिलोथ, धरासू, खटीमा, पथरी में भी विद्युत उत्पादन ठप्प हो गया था। पिथौरागढ़ में धारचूला में भू–स्लखन से एनएचपीसी के 17 श्रमिक फँस गए, जिनको सुरक्षित बाहर निकाला गया।

ज्योतिर्मय में नीति बॉर्डर के मार्ग में सुराईकोठा से दस किलोमीटर आगे तमक का पुल बहने से चीन की सीमा तक सेना का आवागमन अवरुद्ध हो गया। चमोली जिले के गोपेश्वर में नन्दानगर में घरों और दुकानों में दरारें आने से लोग घर छोड़ने को विवश हैं। अतिवृष्टि के कारण जोशीमठ, थराली, मुनिस्यारी, ग्वाल्दम, यमुनोत्री, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, रैणी, भटवाड़ी, धारचूला में भू स्लखन के समाचार हैं। यमुनोत्री मार्ग पर स्यामाचट्टी में हाईवे पर मोटर पुल के ऊपर जल स्तर होने से उसके आसपास बने होटलों में पानी भर गया। एक समाचार के अनुसार अगस्त के अंतिम सप्ताह में 118 सड़कें बंद थीं जिसके कारण सहायता और बचाव कार्य बाधित हुए। रुद्रप्रयाग में बासुकेदार में अतिवृष्टि से दस गांवों में भारी क्षति हुई और आठ लोगों की मृत्यु हो गई। चमोली जिले के देवाल विकासखंड में मोपाटा गांव में अतिवृष्टि के बाद मकान धंस गए जिनमें दो पति पत्नी की मृत्यु हो गई और भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। रुद्रप्रयाग के तालजमान, बगड़तोक और कमदटोक गांवों में अचानक गदेरे में पूरे गांव घिरने से भयानक स्थिति हो गई। घनसाली के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में गेंवाली गांव में भरे नुकसान हुआ और सभी मोटर मार्ग बंद हो गए। कर्णप्रयाग में भी बद्रीनाथ मार्ग से मलबा आने के कारण कमेड़ा, उमटा और चटवापीपल में मार्ग बंद हो गए।

उत्तराखंड में 282 स्वचालित मौसम केंद्र खोलने का निर्णय प्रशंसनीय है। सरकार और नीति निर्माता उत्तराखंड की आपदाओं का जैसा चाहें, इसका आंकलन करें परंतु उत्तराखंड को बचाने के लिए सरकार को धरातल की परिस्थितियों के अनुसार दीर्घकालिक और अल्पकालिक, दोनों उपायों पर विचार करना होगा। उत्तराखंड में फिर से एक बार भूगर्भीय सर्वेक्षणों की रिपोर्ट खंगालनी होंगी और गांवों और नगरों के पुनर्वास को उसी के अनुसार कार्यान्वित करना होगा। ❑❑

विनोद जौहरी, पूर्व अपर आयकर आयुक्त दिल्ली

साधारण से असाधारण बने नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी पचहत्तर वर्ष के हो गये हैं। यह अवसर केवल उनके जीवन की एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति के एक अहम अध्याय का प्रतीक भी है। मोदी का जीवन असाधारण संघर्ष, धैर्य और राजनीति में उत्थान का उदाहरण माना जाता है। बचपन में एक छोटे नगर के स्टेशन पर चाय बेचने वाले लड़के से देश के सर्वोच्च पद तक पहुँचने की उनकी यात्रा ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। नरेन्द्र मोदी का जन्म 17 सितम्बर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर नगर में हुआ। उनका परिवार आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न नहीं था। उनके पिता दामोदरदास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और उसी काम में बचपन से नरेन्द्र मोदी भी हाथ बँटाते थे। शिक्षा के दौरान भी उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। सीमित संसाधनों के बावजूद उनके भीतर आत्मविश्वास और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति बनी रही। किशोरावस्था में ही मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से परिचय मिला। वहीं से राष्ट्रभक्ति, संगठन और अनुशासन के संस्कार उनके भीतर गहरे पैठे। यही संस्कार आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की नींव बने।

यह कहना अतिशियोक्ति नहीं होगी कि भारत के समकालीन इतिहास में नरेन्द्र मोदी का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। उनके समर्थक और आलोचक भले ही अलग–अलग दृष्टिकोण रखते हों, लेकिन यह निर्विवाद है कि मोदी ने राजनीति की दिशा और स्वरूप को बदल डाला है।

–अजय कुमार

नरेन्द्र मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के संगठन कार्य से की। वे चुनाव अभियान चलाने, पार्टी के विस्तार और संगठन खड़ा करने में निपुण समझे जाते थे। गुजरात में पार्टी को मजबूत बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा। 1990 के दशक में वे राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाने लगे और संगठन में विभिन्न दायित्व निभाते रहे। 2001 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के अस्वस्थ होने पर पार्टी ने नरेन्द्र मोदी को राज्य की कमान सौंपी। यही से उनकी राजनीतिक यात्रा ने असली मोड़

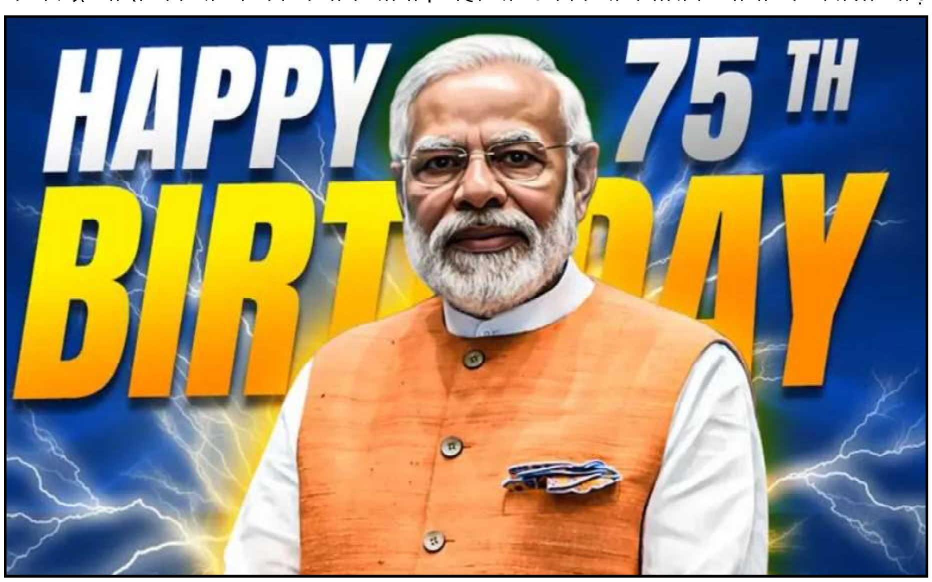

लिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी ने गुजरात में प्रशासन को सुदृढ़ करने, उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा आधारभूत ढाँचे पर बल देने का काम किया। उनके समर्थक मानते हैं कि गुजरात में उनका शासनकाल विकास उन्मुख रहा और राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना। किन्तु 2002 में गुजरात में भयानक दंगे हुए, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। यह घटना नरेन्द्र मोदी से जीवनपर्यंत जुड़ा एक गम्भीर विवाद बन गई। आलोचक मानते रहे कि दंगों को रोकने में प्रशासन विफल रहा, जबकि उनके समर्थक तर्क देते हैं कि मोदी ने शांति बहाल करने के लिए तत्परता से कदम उठाए। यह विवाद आज भी भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है और उनका नाम इस प्रकरण से अनिवार्यतः जोड़ा जाता है।

2013 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उनका अभियान मजबूत नेतृत्व और तेज़ विकास पर केंद्रित था। देशवासी उस दौर में आर्थिक ठहराव और भ्रष्टाचार से त्रस्त थे। मोदी ने जनता में यह विश्वास जगाया कि वे व्यवस्था बदल सकते हैं। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। भारत ने तीन दशकों बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार देखी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने स्वयं को केवल प्रशासक भर नहीं, बल्कि जनसंपर्क में दक्ष नेता के रूप में प्रस्तुत किया। उनके कार्यकाल में अनेक योजनाएँ लागू की गईं, जिनमें गरीबों के लिए आवास, शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना से गरीब परिवारों को रसोई गैस का जोड़ना, जनधन योजना के जरिये खातों का विस्तार और डिजिटल लेन—देन को प्रोत्साहन शामिल है। विदेश नीति में भी मोदी ने सक्रियता दिखाई। उन्होंने विश्व के अनेक देशों की यात्राएँ कीं और भारत की छवि को नये ढंग से प्रस्तुत किया। वे प्रवासी भारतीयों से संवाद करके उन्हें भी भारतीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास करते रहे।

नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे जनता से संवाद स्थापित करने की अनूठी क्षमता रखते हैं। नियमित रूप से वे अपने विचार साझा करने के लिए 'मन की बात' जैसे कार्यक्रम का सहारा लेते हैं। सोशल माध्यमों पर भी उनकी सक्रियता उन्हें नई पीढ़ी से जोड़ती है। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी है जो कठिन निर्णय लेने से नहीं झिझकते।

जहाँ मोदी ने व्यापक जनसमर्थन पाया, वहीं उनके कार्यकाल में कई विवाद भी उभरे। विमुद्रीकरण का निर्णय, जो 2016 में लिया गया, को उन्होंने काले धन और जालसाजी रोकने का कदम बताया, किन्तु इसके कारण आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नोटबंदी के परिणामों पर आज भी मतभेद बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त कृषि सुधार से जुड़े नये नियमों पर देशभर में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए। अंततः सरकार को वे नियम वापस लेने पड़े। इस प्रसंग ने मोदी सरकार को गम्भीर राजनीतिक चुनौतियों का सामना कराया। नागरिकता संशोधन संबंधी विधेयक और अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय भी बहस का कारण बने। समर्थक मानते हैं कि इन कदमों से राष्ट्र की एकता और सुरक्षा सुदृढ़ हुई, जबकि आलोचक इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा मानते रहे विवादों के बावजूद नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता कभी पूरी तरह कम नहीं हुई। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे जनता से संवाद स्थापित करने की अनूठी क्षमता रखते हैं। नियमित रूप से वे अपने विचार साझा करने के लिए 'मन की बात' जैसे कार्यक्रम का सहारा लेते हैं। सोशल माध्यमों पर भी उनकी सक्रियता उन्हें नई पीढ़ी से जोड़ती है। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी है जो कठिन निर्णय लेने से नहीं झिझकते। उनके समर्थक उन्हें देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला नायक बताते हैं, जबकि आलोचक उन्हें केंद्रीकृत सत्ता का प्रतीक मानते हैं।

कुल मिलाकर नरेन्द्र मोदी का पचहत्तर वर्ष का जीवन भारतीय राजनीति की उस यात्रा का प्रतीक है जिसमें संघर्ष, कठिनाइयाँ, सफलता और विवाद सब कुछ समाहित है। वे निश्चय ही इस बात के उदाहरण हैं कि साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी दृढ़ संकल्प, परिश्रम और संघटन क्षमता के बल पर देश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुँच सकता है। उनका योगदान देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज सभी को गहराई से प्रभावित करता रहा है। लेकिन उनके नाम से जुड़े विवाद यह भी दर्शाते हैं कि राजनीति केवल उपलब्धियों का नहीं, बल्कि निरंतर प्रश्नों और आलोचनाओं का भी मंच है। यह कहना अतिशियोक्ति नहीं होगी कि भारत के समकालीन इतिहास में नरेन्द्र मोदी का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। उनके समर्थक और आलोचक भले ही अलग—अलग दृष्टिकोण रखते हों, लेकिन यह निर्विवाद है कि मोदी ने राजनीति की दिशा और स्वरूप को बदल डाला है। पचहत्तर की आयु में भी उनका उत्साह और सक्रियता लाखों लोगों को प्रेरित करती है। ❑❑

सबको पक्का घर का सपना साकार करती प्रधानमंत्री आवास योजना

देश के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर लोगों के सिर पर अपना पक्का छत उपलब्ध कराने के मामले में केंद्र की वर्तमान नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राजग सरकार मैं अपने 10 साल के कार्यकाल में लगभग 3 करोड़ घर लाभार्थियों को देने में कामयाबी पा ली है वही दो करोड़ और नए घरों का लक्ष्य शामिल करते हुए शहरी मध्य वर्ग के लोगों के लिए भी तीन स्लैब के तहत सब्सिडी सुविधा दे रही है। ज्ञात हो कि पूर्व की सरकारों द्वारा 1985 से 2016 के बीच, कुल तीन दशक के समय में इंदिरा आवास योजना के तहत 2,86,88,000 घर बनवाए गए तथा इसके लिए सरकारी खाते से 85,141.13 करोड़ खर्च किए गए थे। यानी कि जो काम पहले 30 साल के लंबे कालखंड में हुए उससे अधिक काम वर्तमान सरकार ने अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाते हुए मात्र 10 साल में कर दिया है।

हर किसी का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण यह सपना अधूरा रह जाता है। पक्का घर' भारत के सबसे निचले तबके के अवचेतन में शायद तब से है, जब सीमेंट खोजी नहीं गई थी और दो ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल होता था। आजादी के बाद से राजनीतिक दलों ने पक्के घर की चाह को अपने पक्ष में जमकर भुनाया है। भारत में गरीबों के लिए मुफ्त सरकारी मकान की योजनाओं का इतिहास लोकतंत्र जितना ही पुराना है। पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने अपने पहले कार्यकाल के आखिर में इसे शुरू कर दिया था। 1957 में भारत में पहली ग्रामीण आवास योजना आई। इसमें सरकार की तरफ से गरीब तबके के लोगों को पक्का घर बनवाने के लिए 5000 रुपए का अनुदान दिया जाता था। 1960 तक देश में इस योजना के तहत पांच लाख आवास बनाए गए। हालांकि बाद में काम की रफ्तार धीमी पड़ती गई। साल 1985 में इस दिशा में दूसरा बड़ा प्रयास शुरू हुआ। राजीव गांधी सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया। इस योजना में भूमिहीन और बंधुआ मजदूरी से मुक्त करवाए गए परिवारों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई थी। इसी योजना के लिए ऐसे परिवारों के लिए 'इंदिरा आवास' नाम से घर बनवाए जाने का प्रस्ताव भी था। शुरुआत में इंदिरा आवास केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ही कवर करती थी। 1993–94 में गैर दलित और आदिवासी बीपीएल परिवारों को भी इस योजना की जद में लाया गया। 1996 लोकसभा में लोकसभा चुनाव होने जा रहे थे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने पहली जनवरी 1996 को इंदिरा आवास योजना को स्वतंत्र योजना घोषित कर दिया। आंकड़ों के मुताबिक 1985 से 2016 के बीच, कुल तीन दशक के समय में इंदिरा आवास योजना के तहत 2,86,88,000 घर बनवाए गए. इसके लिए सरकारी खाते से 85,141.13 करोड़ खर्च किए गए।

2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इंदिरा आवास योजना को नए सिरे से शुरू किया और इसे नाम दिया गया, 'प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत 2022 तक कुल 3 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री की दृष्टि और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए पक्के मकान बनाने और उपलब्ध कराने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण

प्रधानमंत्री आवास योजना ने सुरक्षित आवास प्रदान करके लाखों ग्रामीण परिवारों की जीवन स्थितियों को बदलने में उल्लेखनीय प्रगति की है।

– **शिवनंदन लाल**

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (2015) और ग्रामीण (2016) का शुभारंभ हुआ।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई ग्रामीण) 20 नवंबर 2016 को शुरू की गई, जिसका लक्ष्य समाज के सबसे गरीब वर्गों के लिए आवास प्रदान करना था। लाभार्थियों का चयन कठोर तीन–चरणीय सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जिसमें सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी 2011) और आवास+ (2018) सर्वेक्षण, ग्राम सभा अनुमोदन और जियो–टैगिंग शामिल है। इससे सुनिश्चित होता है कि सहायता सबसे योग्य व्यक्तियों तक पहुंचे। इस योजना में कुशल निधि संवितरण के लिए आईटी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को भी शामिल किया गया है। इसने विभिन्न निर्माण चरणों में जियो–टैग की गई तस्वीरों के माध्यम से क्षेत्र–विशिष्ट, आवास डिजाइन और साक्ष्य–आधारित निगरानी भी लागू की है।

मूल रूप से 2023–24 तक 2.95 करोड़ मकानों को पूरा करने का लक्ष्य रखते हुए, इस योजना को 2 करोड़ और मकानों के साथ बढ़ाया गया, जिसमें वित्त वर्ष 2024–29 के लिए 23,06,137 करोड़ का कुल परिव्यय और वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 54,500 करोड़ का आवंटन किया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 9 अगस्त, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों एवं पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में 1.30 लाख रुपये की मौजूदा इकाई सहायता पर दो करोड़ और मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) के तहत सरकार ने 3.32 करोड़ मकान बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 19 नवंबर,

2024 तक, 3.21 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई है, और 2.67 करोड़ मकान पूरे हो चुके हैं, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों की रहने की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

इस योजना में महिला सशक्तीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें 74 प्रतिशत स्वीकृत मकानों का स्वामित्व पूरी तरह से या संयुक्त रूप से महिलाओं के पास है। यह योजना अब महिलाओं को 100 प्रतिशत स्वामित्व प्रदान करने की आकांक्षा रखती है। कुशल रोजगार भी प्राथमिकता रही है। लगभग 3 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों को आपदा–रोधी निर्माण में प्रशिक्षित किया गया है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई है।

पीएमएवाई–जी ग्रामीण परिवारों के लिए व्यापक सहायता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अन्य सरकारी पहलों के साथ मिलकर काम करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य स्वच्छता, रोजगार, खाना पकाने के ईंधन और जल आपूर्ति जैसी कई जरूरतों को पूरा करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एसबीएम–जी): ग्रामीण घरों में बेहतर स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को शौचालय बनाने के लिए 12,000 तक मिलते हैं। मनरेगा पात्र परिवार अकुशल श्रमिक के रूप में 95 दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के तहत, 290.95 की दैनिक मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना योजना के तहत, प्रत्येक घर मुफ्त एलपीजी कनेक्शन का हकदार है, जो स्वच्छ और सुरक्षित खाना पकाने के ईंधन को बढ़ावा देता है। लाभार्थियों को पाइप्ड पेयजल और बिजली कनेक्शन सुलभ कराने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है और असुरक्षित पानी और अनियमित बिजली आपूर्ति से जुडे स्वास्थ्य जोखिमों में कमी आती है।

पिछले एक दशक में, एसईसीसी 2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई है, और 20 से अधिक राज्यों की आवास+ 2018 सूची भी पूरी हो गई है।

कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना ने सुरक्षित आवास प्रदान करके लाखों ग्रामीण परिवारों की जीवन स्थितियों को बदलने में उल्लेखनीय प्रगति की है। पीएमएवाई– आवास योजना भारत को सशक्त बनाने, सामाजिक समानता सुनिश्चित करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए आंदोलन है। दो करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए हालिया मंजूरी के साथ, सरकार "सभी के लिए आवास" लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता को मजबूत कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र परिवार को गुणवत्तापूर्ण आवास और सम्मानजनक जीवन मिले। ❑❑

(लेखक आकाशवाणी दिल्ली केंद्र के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी है।)

अमरीका से आयी आपदा को अवसर में बदलने का मौका है भारत के पास

निश्चित रूप से अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के लिए वापस लौटने और अपनी स्किल एवं आइडिया से स्वदेश में योगदान देने का मौका है। इससे 'आत्मनिर्भर भारत' मुहिम को भी गति मिलेगी।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

अमरीकी राजनीति हमेशा से संरक्षणवादी रही है। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 'अमेरिका फर्स्ट' के नारे के साथ ही दोबारा सत्ता पर काबिज हुए हैं। अमरीकी राजनीति के जानकारों के बीच वे अवसर के हिसाब से दोहरी चाल के माहिर खिलाड़ी बताये जाते हैं। उनके इस डबल गेम का खामियाजा अमरीका के दोस्त–दुश्मन दोनों पर भारी पड़ता रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति की हरकतों से भारत को भी कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। आलम यह है कि एक तरफ वे भारत–अमरीका के बीच व्यापार समझौते के लिए बातचीत की टेबल पर भी बैठते हैं, तो दूसरी तरफ वे भारत पर अनैतिक रूप से अतिरिक्त टैरिफ लगाने की भी घोषणा कर देते हैं। भारत–पाकिस्तान के बीच हुए हालिया युद्ध के दौरान भी वे अपनी विवादित टिप्पणियों से बाज नहीं आए। बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी यह मानते रहे हैं कि भविष्य की राह को आसान करने के लिए व्यापार समझौता न सिर्फ सूझबूझ वाला कदम है बल्कि दोनों देशों की जरूरत के लिहाज से भी जरूरी है। अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि मंडल बेंडन लिंच की टीम समझौते को अमलीजामा पहनाने के लिए भारत दौरे पर आई थी, वहीं भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अमरीका यात्रा प्रस्तावित है। लग रहा था कि दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एच1बी वीजा पर एक लाख डॉलर की वार्षिक फीस लगाकर भारत को फिर से झटका दे दिया। अमरीका के इस कदम से भारतीय आईटी उद्योग के प्रभावित होने की आशंका है। लेकिन शायद ट्रंप और उनकी टीम यह आकलन करने में चूक कर रही है कि भारत अब दुनिया की गिनी चुनी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत अपनी गौरवशाली चित्ति और मेधा के दम पर देश को आत्मनिर्भर बनाने की राह पर है। अमरीकी प्रशासन ने आर्थिक झटका देने की कोशिश की है लेकिन उसे यह ज्ञान होना चाहिए कि भारत के पास इस आपदा को अवसर में बदलने की सामर्थ्य है।

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच–1बी वीजा शुल्क को बढ़ाकर एक लाख डालर यानी करीब 88 लाख रुपये कर दिया है। हालांकि यह नया नियम केवल नए वीजा आवेदकों पर ही लागू होगा। यह कोई वार्षिक शुल्क नहीं है। जिन लोगों के पास पहले से ही एच–1बी वीजा है और जो इस समय अमेरिका से बाहर हैं, उनसे पुनः प्रवेश के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। ट्रंप ने इस फैसले का बचाव अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए एक उपाय बताते हुए किया है। साथ ही तर्क दिया है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों ने इस कार्यक्रम का इस्तेमाल अमरीकी कर्मचारियों की जगह सस्ते विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए किया है। वहीं कई अमरीकी सांसदों और सामुदायिक नेताओं ने ट्रंप के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और निरर्थक बताते हुए कहा है कि इससे अमरीकी आइटी उद्योग पर बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। यह अमेरिका को उच्चकोटि के कुशल कामगारों से वंचित करने वाला फैसला है। अमेरिका हर साल 65,000 एच–1बी वीजा और 20,000 अतिरिक्त वीजा

देता है। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत वीजा भारतीयों को मिलते हैं। एमेजोन, माइक्रोसाफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों के हजारों कर्मचारी एच–1बी पर वहां काम करते हैं। वहीं कई भारतीय कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल और काग्निजेंट भी अमेरिका में काम करने के लिए इसी वीजा पर काफी निर्भर हैं। ऐसे में कुशल कामगारों को नियुक्त करने वाली छोटी कंपनियां और स्टार्टअप्स ट्रंप के फैसले से मुश्किल में आ जाएंगे। वीजा शुल्क में इस बदलाव से अमेरिका में भारतीय आइटी इंजीनियरों की नौकरियों पर भी खतरा बढ़ेगा।

निश्चित रूप से ट्रंप का यह फैसला भारत के आइटी क्षेत्र और भारतीय प्रतिभाओं के लिए एक आपदा की तरह है, लेकिन यह कई मायनों में अवसर भी बन सकता है। ऐसे आसार हैं कि भारी वीजा शुल्क से अमेरिकी कंपनियां अपनी नौकरियां विदेश यानी भारत जैसे देशों में शिफ्ट करने पर मजबूर हो जाएंगी। ऐसा होने पर ट्रंप की यह नीति अमेरिका के बजाय भारत और दूसरे देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) की स्थापना भी की जा सकती है और इसमें भारत की प्रतिभाओं को अधिक मौके मिलेंगे। जीसीसी जाब मार्केट में नया चलन है। यह आइटी सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, फाइनेंस, एचआर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करती हैं। हाईस्किल युवाओं के होने के कारण भारत जीसीसी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा हब बनता हुआ दिखा रहा है। दुनिया के 50 प्रतिशत जीसीसी सिर्फ भारत में हैं। अभी देश में 1700 जीसीसी हैं जिनसे 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। देश में जीसीसी बाजार का आकार 5.4 लाख करोड़ रुपये का है। 2030 तक इसके 8.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जीडीपी में भारत के जीसीसी का योगदान एक प्रतिशत है और 2030 तक यह 3.5 प्रतिशत हो जाएगा।

एच–1बी वीजा शुल्क बढ़ने से दुनिया की प्रतिभाएं अमेरिका नहीं जा पाएंगी। इससे वहां इनोवेशन भी घट सकती है और भारत के इनोवेशन में नई जान आ सकती है। उम्मीद है पेटेंट, इनोवेशन और स्टार्टअप्स की अगली लहर भारत में तेजी से बढ़ेगी। भारत की प्रतिभाओं के भारत में ही रहने से भारत में शोध एवं विकास की स्थिति मजबूत होगी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआइआइ), 2024 में भारत अभी 39वें स्थान पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट, 2024 के मुताबिक भारत ने तीन प्रमुख बौद्धिक संपदा अधिकारों (आइपी)–पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों के लिए विश्व के शीर्ष 10 देशों में स्थान प्राप्त किया है। अब अमेरिकी आइटी कंपनियां भारतीय कंपनियों को ज्यादा आउटसोर्सिंग का काम दे सकती हैं। इससे भारत से अमेरिका के लिए काम बढ़ेंगे। भारत ग्लोबल आउटसोर्सिंग का नया हब बनने की डगर पर आगे बढ़ सकेगा। पिछले कई वर्षों से आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में भारत की प्रगति के पीछे देश में संचार का मजबूत ढांचा होना एक प्रमुख कारण है। दूरसंचार उद्योग के निजीकरण से नई कंपनियों के अस्तित्व में आने से दूरसंचार की दरों में भारी गिरावट आई है। उच्च कोटि की त्वरित सेवा, आइटी एक्सपर्ट और अंग्रेजी में पारंगत युवाओं की बड़ी संख्या ऐसे अन्य कारण हैं, जिनकी बदौलत भारत पूरे विश्व में आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है।

निश्चित रूप से अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के लिए वापस लौटने और अपनी स्किल एवं आइडिया से स्वदेश में योगदान देने का मौका है। इससे 'आत्मनिर्भर भारत' मुहिम को भी गति मिलेगी। ट्रंप द्वारा लगाई गई ऊंची फीस की आपदा को अवसर में बदलने के लिए हमें अन्य कई बातों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे कि आउटसोर्सिंग के लिए अमेरिकी बाजार के साथ–साथ यूरोप और एशिया–प्रशांत क्षेत्र में नई व्यापक संभावनाओं को मुट्ठियों में लेना होगा। इसके लिए हमें देश में आउटसोर्सिंग के चमकीले भविष्य के लिए प्रतिभा निर्माण पर जोर देना होगा। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि साफ्टवेयर उद्योग में हमारी अगुआई की मुख्य वजह हमारी सेवाओं और प्रोग्राम का सस्ता होना है। अतः इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए हमें तकनीकी रूप से दक्ष लोगों की उपलब्धता बनाए रखनी होगी। ❑❑

मर्यादित अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है पारिवारिक गौरव

भारतीय समाज में लक्ष्मण रेखा शब्द अत्यंत उपयुक्त है और यह अर्थव्यवस्था पर भी उतना ही लागू होता है।
– प्रो. गौरी पिंपले

मर्यादा और अर्थव्यवस्था पर विचार करते समय एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में आई–जहाँ परिवार व्यवस्था मजबूत है वहाँ जिम्मेदारी की भावना होती है। इसी कारण एशियाई देशों में बचत का अनुपात यूरोपीय देशों या अमेरिका से अधिक रहा है। और इन एशियाई देशों की विशेषता यह है कि यह बचत अलग–अलग प्रकार से घरेलू निवेश के लिए प्रयोग की जाती है और इसी कारण ये देश समृद्ध होते हैं। विशेष रूप से 1970 के बाद यह देखा गया कि एशियाई देश अधिक बचत की आदत के कारण अधिक प्रगति कर रहे हैं।

1991 में जब वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, तब पूँजी की स्वतंत्र आवाजाही शुरू हुई। पूँजी बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति वैश्वीकरण के बाद दी गई। इससे यह हुआ कि एक देश में जो बचत हो रही थी वह बचत दूसरे देश में मोड़ दी गई। अलग–अलग देशों की बचत अलग–अलग प्रकार से निवेशित हुई। इसलिए यदि किसी देश ने अपनी अर्थव्यवस्था में अनुशासन नहीं रखा तो उसका असर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप से 1991 के बाद वैश्वीकरण के पश्चात, सभी देश एक–दूसरे से ऐसे जुड़ गए कि किसी एक देश में हुई उथल–पुथल का झटका दूसरे देशों को भी लगा। एशियाई देशों में बचत का अनुपात अधिक था, इसलिए निवेश अधिक हुआ, और वे देश तेज़ी से प्रगति कर रहे थे। उस समय यूरोपीय देशों से बड़े पैमाने पर निवेश आया। लेकिन यह निवेश आने के बाद, जिस तेजी से आया उसी तेजी से जब किसी देश को झटका लगा तो निकाल लिया गया। इसका उत्तम उदाहरण 1997 में है, जब पूर्व एशियाई देश–जिन्हें उस समय टाइगर इकॉनॉमीज़ कहा जाता था–बड़े आर्थिक संकट में फँस गए और विदेशी निवेशकों ने बहुत तेजी से अपनी पूँजी बाहर निकाल ली।

जून 1997 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इन पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं की प्रशंसा की थी, लेकिन जुलाई 1997 में वही अर्थव्यवस्थाएँ ढह गईं। किसी भी विशेषज्ञ को इसका अंदाज़ा तक नहीं था? आइए देखें कि ईस्ट एशियन क्राइसिस क्या था।

आयात–निर्यात के व्यापार में, यदि निर्यात अधिक हो तो व्यापार लाभ होता है। डॉलर में मिलने वाले इस लाभ का कुछ भाग अपने देश में निवेश किया जाता है और कुछ भाग पुनः डॉलर में निवेशित किया जाता है (इसमें मुद्रा भंडार भी आता है)। यदि कठिन आर्थिक परिस्थिति आती है तो यह निवेश काम आता है। इसमें यह मानकर चला जाता है कि देश का विनिमय दर वही रहेगा।

अब एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक मुद्रा 'क्ष' है। उसका मूल्य है 1 डॉलर = 10 क्ष। यहाँ यदि 10,000 डॉलर का लाभ हुआ तो क्ष मुद्रा में वह 10,000 गुणा 10 = 100,000 क्ष होगा। यदि क्ष मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाए, 1 डॉलर = 15 क्ष, तो उपरोक्त लेनदेन में होने वाला लाभ 10,000 गुणा 15 = 150,000 क्ष होगा। विनिमय दर में इस अंतर से निर्यातक देशों को ऐसा लाभ होता है। (इसलिए सामान्यतः अधिकांश देशों का झुकाव ऐसा अंतर बनाए रखने का होता है)।

1990 में यूएसएसआर (रूस) का विघटन हुआ और वैश्विक परिदृश्य पर अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति रह गया। तब तक डॉलर की स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत हो

चुकी थी। निर्यातक देशों ने अधिक से अधिक निर्यात करके डॉलर में होने वाली आय बढ़ानी शुरू कर दी। इसमें पूर्व एशियाई देश अग्रणी थे (थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपीन्स, दक्षिण कोरिया)। ये पूँजीगत वस्तुएँ आयात करते और उपभोक्ता वस्तुएँ निर्यात करते।

इन देशों की मुद्रा विनिमय दर कम थी (अवमूल्यित)। इसलिए उन्हें होने वाला लाभ उनकी अपनी मुद्रा में बहुत अधिक था। यही लाभ पुनः घरेलू व्यापार, अधोसंरचना परियोजनाओं, बड़े उद्योगों, सरकारी प्रतिष्ठानों में निवेशित हुआ। इन देशों की अर्थव्यवस्था तेज़ी से प्रगति करने लगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक ने इन देशों की प्रशंसा की। ये देश 'टाइगर इकॉनॉमीज़' कहलाने लगे।

अच्छी अर्थव्यवस्था के कारण इन देशों में विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इन देशों के शेयर बाजार ऊपर गए, रियल एस्टेट क्षेत्र की कीमतें ऊँची बनी रहीं, उद्योगों को गति मिली।

इसी दौरान, 1994 में चीन ने युआन का अवमूल्यन किया। इससे इन देशों की मुद्रा विनिमय दर बढ़ी। अर्थात् डॉलर और इन देशों की मुद्रा के बीच का अंतर घटा। इसलिए इन देशों को झटका लगने लगा। थाईलैंड को डॉलर बेचकर अपनी मुद्रा को स्थिर करना पड़ रहा था और एक समय ऐसा आया जब थाईलैंड के पास डॉलर शेष नहीं बचे। 2 जुलाई 1997 को थाईलैंड ने घोषणा की–"अब थाईलैंड की मुद्रा डॉलर से जुड़ी नहीं है"। तुरंत ही विदेशी निवेशकों ने अपनी पूँजी निकाल ली। थाईलैंड ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया। थाईलैंड के साथ ही अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाएँ भी ढह गईं। इसमें मलेशिया, फिलीपीन्स, दक्षिण कोरिया से भी विदेशी पूँजी निकाल ली गई। इन देशों ने अपनी मुद्राओं का 30 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अवमूल्यन किया। इसका असर अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर भी हुआ। रूस और ब्राज़ील इनसे बुरी तरह प्रभावित हुए। इस घटना को ईस्ट एशियन क्राइसिस 1997 कहा जाता है।

1997 की इस घटना के बाद जापान ने आईएमएफ से यह माँग की कि एशियन मॉनेटरी फंड (एएमएफ) स्थापित किया जाए। इसके लिए जापान स्वयं 100 बिलियन डॉलर देने को तैयार था, लेकिन आईएमएफ ने इस माँग को ठुकरा दिया।

उस समय मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथीर मोहम्मद ने अत्यंत जिम्मेदारी और गंभीरता से यह वक्तव्य दिया कि यह चाल हमारी अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए रचा गया एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। उस समय वैश्विक मीडिया ने इस वक्तव्य को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। इसके विपरीत, विश्वभर में यह प्रचारित किया गया कि इन देशों की आर्थिक नीतियाँ गलत थीं और उसी का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कुछ घटनाएँ ऐसी हुईं जिनसे महाथीर मोहम्मद के बयान को पुष्टता मिली।

जून 1997 में जब आईएमएफ ने इन देशों की प्रशंसा की थी, तब आईएमएफ को विश्वास था कि ये देश अन्य देशों को पीछे छोड़कर मजबूत अर्थव्यवस्था बनाएँगे। लेकिन अचानक इन देशों की साख गिर गई। पूँजी निवेशकों ने निवेश निकालना शुरू कर दिया। वैश्विक संगठनों ने घोषित किया कि इन देशों की नीतियाँ गलत थीं। लेकिन मूल मुद्दा डॉलर–केंद्रित अर्थव्यवस्था ही था। डॉलर की आपूर्ति अचानक कम हो गई और अर्थव्यवस्थाएँ ढह गईं। इसके बाद आईएमएफ ने इन देशों के लिए बेल–आउट पैकेज घोषित किए। उन पर कड़े आर्थिक नियम लगाए गए। इनके माध्यम से ये अर्थव्यवस्थाएँ धीरे–धीरे सामान्य हुईं।

हालाँकि ये अर्थव्यवस्थाएँ सामान्य हो गईं, लेकिन कुछ प्रश्न अनुत्तरित रहे। क्या यह सचमुच षड्यंत्र था? क्या अमेरिका की स्थिति और अधिक मजबूत करने के लिए यह चाल चली गई? क्या अतिरिक्त पूँजी के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर इन देशों में मुद्रास्फीति दर अधिक रखना और पश्चिमी देशों में मुद्रास्फीति दर कम रखना, ऐसी व्यवस्था जानबूझकर की गई? क्या इस मुद्रा संकट के कारण डॉलर का मूल्य बढ़े और मुद्रा भंडार में डॉलर का अनुपात बढ़े, यही उद्देश्य था? क्या वैश्विक संगठनों की इच्छा थी कि एशियाई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करें?

1997 की इस घटना के बाद जापान ने आईएमएफ से यह माँग की कि एशियन मॉनेटरी फंड (एएमएफ) स्थापित किया जाए। इसके लिए जापान स्वयं 100 बिलियन डॉलर देने को तैयार था, लेकिन आईएमएफ ने इस माँग को ठुकरा दिया। (क्योंकि आईएमएफ, विश्व बैंक के मुख्यालय अमेरिका में हैं और अमेरिका के पास वीटो पावर है)।

ये अर्थव्यवस्थाएँ अपने देश में मौजूद बचत की ताकत पर खड़ी हुईं। लेकिन वैश्वीकरण ने जब अर्थव्यवस्थाओं को एक–दूसरे पर आश्रित बना दिया था, तो बाद में लगे झटके से उबरने में कुछ वर्ष लग गए।

भारतीय समाज में लक्ष्मण रेखा शब्द अत्यंत उपयुक्त है और यह अर्थव्यवस्था पर भी उतना ही लागू होता है। ❑❑

प्रो. गौरी पिंपळे– प्राध्यापिका, मुंबई विद्यापीठ।

वर्तमान वैश्विक नेतृत्व में विश्व कल्याण के भाव का अभाव

आज विश्व के कुछ देशों में सत्ता उस विचारधारा के दलों के पास आ गई है जो शक्ति के मद में चूर हैं एवं अपने लिए प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं। उनके विचारों में विश्व कल्याण की भावना का पूर्णतः अभाव है। इन देशों के नेतृत्व की कार्यप्रणाली से कुछ देशों के बीच आपस में टकराव पैदा होता दिखाई दे रहा है। दो देशों के बीच की समस्याओं को हल करने के प्रयास के स्थान पर किसी एक देश का पक्ष लेकर दूसरे देश के विरुद्ध खड़े हो जाना भी इन देशों की कार्यप्रणाली का हिस्सा बनता जा रहा है। इस कार्यप्रणाली से कुछ देशों के बीच आपस में युद्ध की स्थिति निर्मित हो रही है। इजराईल एवं ईरान के बीच एवं रूस एवं यूक्रेन के बीच तथा कम्बोडिया एवं थाईलैंड के बीच छिड़ा हुआ युद्ध इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दरअसल, दो देशों के बीच युद्ध छिड़ने से चौधराहट करने वाले देशों द्वारा अपने देश में निर्मित हथियारों को युद्ध करने वाले देशों को बेचा जाता है जिससे इन देशों में प्रभावशाली लाबी संतुष्ट होती है और वह इन देशों में चुनाव के समय राजनैतिक दलों की मदद करने का प्रयास करती है। पूंजीवादी देशों में कोरपोरेट जगत द्वारा ही सत्ता की स्थापना की जाती है। सत्ता प्राप्त करने के बाद इन्हीं राजनैतिक दलों द्वारा इस कोरपोरेट जगत के हितों को साधने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार इन देशों में राजनैतिक दलों एवं कोरपोरेट जगत का एक नेक्सस अपने अपने हितों का ध्यान रखने के लिए सक्रिय रहता है। अमेरिका में भी आज यही स्थिति दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में हथियारों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों की, वर्तमान सत्ता के गलियारे में, अच्छी पैठ दिखाई देती है।

वर्तमान वैश्विक नेतृत्व द्वारा विश्व कल्याण पर विचार किए जाने एवं छोटे छोटे अविकसित एवं विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं की सहायता किए जाने के स्थान पर अन्य देशों, जिनके नेता इन तथाकथित विकसित देशों की अमानवीय शर्तों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद किये जाने की धमकियां तक दी जा रही हैं। यूरोपीयन यूनियन के अध्यक्ष ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की धमकी इसलिए दी है क्योंकि भारत, रूस से कच्चे तेल का आयात करता है। इसी प्रकार, ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारत एवं रूस की अर्थव्यवस्थाओं को मृत अर्थव्यवस्था की श्रेणी का बताया है एवं भारत द्वारा अमेरिका में किए जाने वाले निर्यात पर 25 प्रतिशत का टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू कर दिया है क्योंकि भारत, रूस से कच्चे तेल एवं सुरक्षा उपकरणों का भारी मात्रा में आयात करता है। जबकि, भारत एवं अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार संधि अपने अंतिम चरण में हैं।

भारत का विश्व गुरु बनना केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के भले के लिए भी आवश्यक है।

— **प्रहलाद सबनानी**

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय श्री गुरुजी (श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर) ने आज से 65–70 वर्ष पूर्व ही साम्यवादी एवं पूंजीवादी विचारधारा पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि "न तो साम्यवाद और न ही पूंजीवाद संसार को एक सूत्र में बांध सकेंगे। इसके पीछे उन्होंने कुछ बुनियादी कारण बताए थे। भौतिकवादी दर्शन, जो मनुष्य को एक प्राणी मात्र समझता है और मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ही सर्वोच्च लक्ष्य मानता है, वह मनुष्य में स्पर्धा और संघर्ष का भाव तो उत्पन्न कर सकता है, उसमें एकता और सौहार्द पैदा नहीं कर सकता। कारण स्पष्ट है — भौतिकता की

भूमि पर मतभेद और मार्गों की भिन्नता अनिवार्य हो जाती है। वे अलगाव और वर्चस्व की धारा को बल प्रदान करते हैं। जो लोग संसार को भौतिकता के यथार्थ से देखते हैं उनके लिए समन्वय और एकात्मता का कोई महत्व नहीं है। वे सहयोग के विषय में सोच ही नहीं सकते। यह तो भारत की दृष्टि है, जब हम इन विभिन्नताओं के भीतर छिपी आंतरिक एकता का अनुभव करते हैं, जब हम सम्पूर्ण एकात्मता की अनुभूति कर पाते हैं। भौतिकवादी दृष्टिकोण में हम अपना अलग और बिरला अस्तित्व समझने लगते हैं, जिनमें पारस्परिक प्रेम और अपनत्व का कोई स्थान नहीं होता। ऐसे प्राणियों में अपनी स्वार्थपरता पर नियंत्रण करने और समस्त मानवजाति की भलाई में बाधक तत्वों को नष्ट करने की भी कोई प्रेरणा नहीं होती हैं।" आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की सत्ता में बैठे विभिन्न राजनैतिक दलों की स्थिति को देखते हुए, 65—70 वर्ष पूर्व प्रकट किए गए पूजनीय गुरुजी के उक्त विचार आज कितने सटीक बैठते हैं।

पूजनीय श्री गुरुजी का यह दृढ़ विश्वास था कि भारतीय जीवन पद्धति ही एक मात्र ऐसी पद्धति है जो सामाजिक विकास को अवरुद्ध किए बिना वैयक्तिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। पश्चिमी दर्शन दो पद्धतियों पर विश्वास करता है — लोकतंत्र और साम्यवाद। लोकतंत्र ने स्वार्थ परता को बढ़ावा दिया और एक मनुष्य को दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। यह सर्वविदित है। इसमें मनुष्य के लिए कहीं भी शांति नहीं है। इस व्यवस्था में आध्यात्मिकता के विकास का कोई अवसर अथवा मार्ग नहीं है। आत्म—प्रशंसा और पर निंदा जो प्रायः चुनावों के समय देखी जा सकती है, आध्यात्मिकता की हत्या कर देती है। यह विचार भारत की वर्तमान राजनैतिक स्थिति पर भी सटीक बैठते हैं। दूसरी ओर, साम्यवाद मस्तिष्क को एक ही विचारधारा से ग्रसित कर देता है। यह मनुष्य की वैयक्तिकता का विनाश कर देता है किन्तु मनुष्य केवल पशु नहीं है जो खाते पीते है और संतानोत्पति मात्र करते हैं। मनुष्य में सोचने, विचारने, चिंतन एवं मनन करने की शक्ति भी होती है जिसके माध्यम से कर्म एवं अर्थ सम्बंधी कार्य को धर्म के साथ जोड़कर सम्पन्न करने की क्षमता विकसित होती है। इस शक्ति को भौतिक वस्तुओं की सम्पन्नता के बीच भी प्राप्त किया जा सकता है यदि व्यक्ति का झुकाव आध्यात्म की ओर हो।

पूंजीवादी एवं साम्यवादी विचारधारा के ठीक विपरीत भारतीय दर्शन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक एकता को परस्पर आश्रितता के माध्यम से दोनों को ही सुनिश्चित किया गया है। प्राचीन काल में भारत के नागरिक आर्थिक दबाव से मुक्त रहते थे, क्योंकि किसी भी परिवार में शिशु के जन्म के साथ ही उसे एक पुश्तैनी व्यवसाय को चलायमान रखने की गारंटी रहती थी। उस खंडकाल में परिवार में पुश्तैनी व्यवसाय को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी के कंधो पर रहती थी। अतः युवा पीढ़ी पर आर्थिक दृष्टि से दबाव अथवा तनाव नहीं रहता था। अब तो पश्चिमी दार्शनिक भी भारतीय आर्थिक दर्शन के विभिन्न आयामों पर गम्भीरता से विचार करने लगे हैं। दरअसल, इसी पद्धति के चलते भारत में वर्ण व्यवस्था (क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्राह्मण) पनपी थी जिसे बाद में अंग्रेजों ने दुर्भावनावश जाति व्यवस्था का नाम दे दिया था तथा हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के नाम पर तथाकथित विभिन्न जातियों (अंग्रेजी शासन की देन) के बीच आपस में मतभेद पैदा करने में सफलता पाई थी ताकि उन्हें भारत पर अपना शासन स्थापित करने में आसानी हो।

पूंजीवादी एवं साम्यवादी विचारधारा के ठीक विपरीत भारतीय दर्शन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक एकता को परस्पर आश्रितता के माध्यम से ही सुनिश्चित किया गया है।

वैश्विक स्तर पर पूंजीवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं में आ रही समस्याओं के समाधान में असफल रहने के बाद अब कई देश भारत के दर्शन पर रिसर्च कर रहे हैं एवं इस व्यवस्था को अपने देश में लागू करने पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लगातार इस बात को दोहराता रहा है कि सनातन हिंदू संस्कृति के संस्कारों से ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। अतः भारत का विश्व गुरु बनना केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के भले के लिए भी आवश्यक है। भारत में पनपी हिंदू सनातन संस्कृति मनुष्य को सांसारिक आवश्यकताओं से चिंतामुक्त करके ईश्वरोन्मुखी बनाती है। भारत में समस्त वर्णों में उच्च श्रेणी के संत महात्माओं का जन्म हुआ है। यही कारण है कि सभी जातियों में आध्यात्मिकता के आधार स्तम्भ पर खड़ा यह एक आश्चर्यजनक लोकतंत्र है। इस पृष्ठभूमि में भारत में सभी नागरिक समान और एकात्म हैं। इसी आध्यात्म के बल पर कालांतर में भारत विश्व गुरु बन गया था। आज के परिप्रेक्ष्य में एक बार पुनः पूरे विश्व को भारतीय आध्यात्म की आवश्यकता है। ❑❑

प्रहलाद सबनानी, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक, ग्वालियर, म.प्र.

प्रकृति से खिलवाड़ के खतरनाक नतीजे

भारतीय दर्शन के अनुसार, मानव सभ्यता का विकास हिमालय और उसकी नदी घाटियों से माना जाता है। आज विकास के तरीकों और जल्दबाजी से समूचे हिमालय के दरकने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली गांव समेत तीन स्थानों पर आई प्राकृतिक आपदा एक चेतावनी है कि प्रकृति से खिलवाड़ के नतीजे भयानक हो सकते हैं। धराली और हर्षिल में बाढ़ के रूप में प्रकृति ने जो दृश्य दिखाए हैं, वे वास्तव में भयावह हैं। एक बार फिर चारधाम यात्रा से जुड़े इस मार्ग पर केदारनाथ आपदा की कहानी प्रकृति है।

दरअसल, वर्तमान में समूचा हिमालयी क्षेत्र आधुनिक विकास और जलवायु परिवर्तन के खतरों से दो–चार हो रहा है। मौसम और प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देने वाले उपग्रह चाहे जितने आधुनिक तकनीक से जुड़े हों, वे अनियमित हो चुके मौसम के कारण बादलों के फटने, हिमनदों के टूटने और भारी बारिश होने की क्षेत्रवार सटीक जानकारी नहीं के टूटने दे पाते हैं। वर्ष 2013 में केदारनाथ त्रासदी और 2014 में जम्मू–कश्मीर की नदियों में बाढ़ आने के संकेत भी उपग्रह से नहीं मिल पाए थे। इसी तरह वर्ष 2021 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के निकट हिमनद के टूटने से तबाही मची थी। इससे धौलीगंगा नदी में अचानक बाढ़ आई और तपोवन पनबिजली परियोजना में काम कर रहे अनेक मजदूर काल के गाल में समा गए थे। हिमाचल प्रदेश में भी भू–स्खलन, बादल फटने और भारी बारिश से तबाही देखने में आ रही है।

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस बार मानसून में लंबी बाधा के कारण देश के कुछ हिस्सों में कम बारिश से सूखे जैसे हालात निर्मित हो हैं, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश तबाही मचा रही है। मानसून में रुकावट आ जाने से बादल पहाड़ों पर इकट्ठे हो जाते हैं और यही मूसलाधार बारिश के कारण बनते हैं। मगर तबाही के लिए मानसून को जिम्मेदार ठहरा कर जवाबदेही से नहीं बचा सकता। केदारनाथ में बिना मानसून की रुकावट के ही तबाही आ गई थी। इसलिए यह कहना बेमानी है कि मानसून की रुकावट

पूरे हिमालय क्षेत्र में अंधाधुंध विकास की परियोजनाएं हिमालय की आंतरिक सुगठित संरचना को नष्ट कर रही है।

– विजय गर्ग

उत्तराखंड भूकम्प के सबसे खतरनाक जोन–5 में आता है। कम तीव्रता के भूकम्प यहां निरंतर आते रहते हैं। मानसून के दौरान हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भू–स्खलन, बादल फटने और बिजली गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

तबाही में बदली। असल में समूचे हिमालय क्षेत्र में बीते एक दशक से पर्यटकों के लिए सुविधाएं जुटाने तथा जल विद्युत और रेल परियोजनाओं के कार्यों में प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है। इन परियोजनाओं के लिए हिमालय क्षेत्र में रेल गुजारने और कई हिमालयी छोटी नदियों को बड़ी नदियों में मिलाने के लिए सुरंगें निर्मित की जा रही हैं। बिजली परियोजनाओं के लिए भी जो संयंत्र लग रहे हैं, उनके लिए हिमालय को खोखला किया जा रहा है।

आधुनिक औद्योगिक और प्रौद्योगिकी विकास में असंतुलन का ही परिणाम है कि आज पहाड़ दरकने लगे हैं, जिन पर हजारों वर्ष से मनुष्य अपनी ज्ञान परंपरा के बूते जीवन यापन करने के साथ हिमालय और वहां रहने वाले अन्य जीव जगत की भी रक्षा करता रहा था हिमालय और पृथ्वी सुरक्षित बने रहें, इस दृष्टि से कृतज्ञ मनुष्य ने अथर्ववेद में लिखे पृथ्वी सूक्त में अनेक प्रार्थनाएं की हैं। इसमें राष्ट्रीय अवधारणा एवं 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना को पोषित एवं फलित करने के लिए मनुष्य को नीति और धर्म से बांधने की कोशिश की है, लेकिन हमने कथित भौतिक सुविधाओं के लिए अपने आधार को ही नष्ट करने का काम आधुनिक विकास के बहाने कर दिया।

आपदा प्रभावित धराली और हर्षिल क्षेत्र में बहने वाली भागीरथी नदी पर बनी 1300 मीटर लंबी और 80 मीटर चौड़ी झील से पानी का रिसाव हो रहा है, इसे पोकलैंड मशीनों से तोड़ने की तैयारी है, ताकि रिसाव के लिए थोड़ा प्रवाह बढ़ जाए और झील का जलस्तर घट जाए। अगर इस झील के बीच कोई बड़ा बोल्डर होगा, तो इसे नियंत्रित विस्फोटक से तोड़ा जाएगा। पहाड़ों में अतिवृष्टि के चलते यह झील अस्तित्व में आ गई है। हिमालय में झील, तालाब और हिमनदों का बनना एक आश्चर्यजनक, लेकिन स्वाभाविक प्रक्रिया है। चूंकि यह झील हर्षिल और धराली के लिए संकट बन गई है, लिहाजा इसे तोड़ा जाना जरूरी हो गया है। अगर यह प्राकृतिक प्रकोप के चलते टूटती है, तो धराली एवं हर्षिल को और खतरा बढ़ जाएगा। देहरादून सिंचाई विभाग के अभियंताओं का बारह सदस्यीय दल हेलिकाप्टर से झील के निरीक्षण में लगा है। झील के प्रवाह में यदि कोई चट्टान बाधा है, तो उसे रिमोट से नियंत्रित विस्फोटक से तोड़ा जाएगा। इस विधि से वही हिस्सा टूटता है, जितना तोड़ना जरूरी होता है। हालांकि अभी तक यह निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सका है. इस जल प्रलय का वास्तविक कारण क्या है। भू–विज्ञानी असमंजस में हैं। सच्चाई जानने के लिए वे अब 'रिमोट सेंसिंग डेटा' और 'सेटेलाइट डेटा' की प्रतीक्षा में है। इससे स्थिति साफ होगी कि खीर गंगा नदी में आया सैलाब बादल फटने, हिमनद टूटने या भू–स्खलन से आया या फिर किसी अन्य कारण से। इस सिलसिले में भू–विज्ञानियों और विशेषज्ञों का मानना कि नदी में अचानक इतना सैलाब किस कारण से आया, यह कहना फिलहाल संभव नहीं है। यह आपदा प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही कारण से हो सकती है। इन विरोधाभासी अनुमानों से साफ है कि इस बार आई आपदा के बारे में कारण स्पष्ट नहीं है। दरअसल, पर्वतीय क्षेत्रों में प्रकृति के साथ संतुलन बना कर विकास कार्य होना चाहिए, लेकिन कथित विकास की चकाचौंध में राज्य सरकारें कोई संतुलित नीति बना भी लेती हैं, तो उसके क्रियान्वयन में ईमानदारी नहीं बरतती हैं। यही वजह है पूरे हिमालय क्षेत्र में अंधाधुंध विकास की परियोजनाएं हिमालय की आंतरिक सुगठित संरचना को नष्ट कर रही है।

इस आपदा ने यह साफ कर दिया है कि उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में झीलों के खतरे बढ़ रहे हैं। राज्य में ऐसी करीब 1266 झीलें हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने उत्तराखंड में 13 हिमनदों को खतरनाक श्रेणी के रूप में चिह्नित किया है। इनमें से पांच को उच्च जोखिम श्रेणी में रखा है। हालांकि यह मुद्दा कोई नया नहीं है। वर्ष 2013 में केदारनाथ जल प्रलय के बाद मुद्दा महत्त्वपूर्ण हो गया था।

उत्तराखंड भूकम्प के सबसे खतरनाक जोन–5 में आता है। कम तीव्रता के भूकम्प यहां निरंतर आते रहते हैं। मानसून के दौरान हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भू–स्खलन, बादल फटने और बिजली गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पहाड़ों के दुरकने के साथ हल्के भूकम्प भी आ रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में बीते सात वर्षों में 130 बार से ज्यादा छोटे भूकम्प आए हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में जल विद्युत और रेल परियोजनाओं ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। टिहरी पर बांध को रोकने के लिए तो लंबा अभियान चला था। पर्यावरणविद और भू–वैज्ञानिक भी हिदायतें देते रहे हैं कि गंगा और उसकी सहायक नदियों की अविरल धारा बाधित हुई, तो फिर गंगा तो अस्तित्व खोएगी ही, हिमालय की अन्य नदियों और झीलों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। ❑❑

विजय गर्ग, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, मलोट, पंजाब

भावनाएं भड़काने वाली राजनीति से रहना होगा सावधान

श्रीनगर की प्रसिद्ध हज़रतबल दरगाह के जीर्णोद्धार पट्टिका पर राष्ट्रीय प्रतीक की उपस्थिति ने ईद–ए–मिलाद (पैगंबर का जन्मदिन, 5 सितंबर) पर मस्जिद जाने वाले कश्मीरी मुसलमानों में आक्रोश भड़का दिया और अशोक चक्र को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की घटना ने पूरे देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। यह मुद्दा इस्लाम के भीतर और इस्लाम–व–ग़ैर–इस्लाम के भीतर की संवेदनशीलताओं से जुड़ा है। चूँकि राजनीति इस विवाद में शामिल हो गई है, इसलिए इस विषय की निष्पक्ष जाँच ज़रूरी है।

जम्मू और कश्मीर वक़्फ़ बोर्ड ने अस्सरी शरीफ हजरतबल दरगाह का जीर्णोद्धार करवाया। इसका उद्‌घाटन 3 सितंबर, 2025 को जम्मू–कश्मीर वक़्फ़ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. सैयद दरख्शां अंद्राबी ने किया। पट्टिका पर अंकित अन्य सदस्यों में सैयद मोहम्मद हुसैन, डॉ. गुलाम नबी हलीम, बोर्ड के तहसीलदार इश्तियाक मोहिउद्दीन और इंजीनियर सैयद गुलाम ए मुर्तजा के नाम शामिल हैं। पट्टिका के शीर्ष पर, बीच में एक उर्दू पाठ है, दाहिनी ओर अर्धचंद्र के ऊपर मस्जिद का चित्र है, और बाईं तरफ उसी आकार का एक अशोक चक्र है। न तो यह पट्टिका और न ही उस पर अंकित कोई भी वस्तु पूजा की वस्तु थी और न ही है। यह निश्चित है कि अशोक चक्र पर 3 सितंबर को ही ध्यान दिया गया था। फिर भी, 3 या 4 सितंबर को असहमति की कोई आवाज़ तक नहीं उठी। 5 सितंबर को ही विरोध प्रकट किया गया, जब पहले पुरुषों के एक समूह ने और फिर महिलाओं के एक समूह ने एक भारी पत्थर से प्रतीक को मिटा दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्रवाई सोच–समझकर की गई थी। राजनीतिक नेताओं द्वारा हिंसा का बचाव, जो इस मामले को बोर्ड या राज्यपाल के समक्ष निजी तौर पर उठा सकते थे, ने पूरे देश में भावनाओं को भड़का दिया है। यह तर्क कि राजधानी पर बने शेर प्रतीकात्मक हैं और दरगाह के धार्मिक मूल्यों के साथ असंगत हैं, खोखला लगता है।

भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को खाड़ी के कुछ इस्लामी देश, जहां इस्लाम का जन्म हुआ था, से सीख लेनी चाहिए जो एक उदार धर्म का समर्थन कर रहे हैं।

– संध्या जैन

हज़रतबल दरगाह की प्रसिद्धि एक पवित्र अवशेष, पैगंबर मुहम्मद की दाढ़ी के एक बाल, जिसे मोई–ए–मुक़द्दस कहा जाता है, के कारण है। इसे पैगंबर के व्यक्तिगत प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता है, हालाँकि इसकी औपचारिक रूप से पूजा नहीं की जाती। सवाल उठता है कि क्या अशोक चक्र को गणतंत्र के प्रतीक के रूप में उस पट्टिका पर सम्मान नहीं दिया जा सकता था, जहां उसकी औपचारिक रूप से पूजा नहीं कि जा रही थी? अंद्राबी ने इस तोड़फोड़ की निंदा करते हुए इसे एक "आतंकवादी हमला" और संविधान, दरगाह की गरिमा और राष्ट्रीय प्रतीकों पर हमला बताया। उन्होंने इस उपद्रव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को ज़िम्मेदार ठहराया और इसे वक़्फ़ बोर्ड पर नियंत्रण न रख पाने की उनकी हताशा से जोड़ा।

इस कथन में कुछ दम हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने मस्जिदों और दरगाहों पर नियंत्रण करके और उन्हें वक्फ बोर्ड के अधीन लाकर कश्मीरी मुसलमानों के प्रमुख नेता के रूप में अपनी सार्वजनिक छवि बनाई थी। यह उनकी शक्ति का आधार स्तंभ था। शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को बोर्ड पर नियंत्रण नहीं होने का अफ़सोस है।

जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस तोड़फोड़ का समर्थन किया, धार्मिक स्थल पर अशोक चिह्न लगाने पर सवाल उठाया और तोड़फोड़ में शामिल लोगों पर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) लगाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला ने वर्तमान हज़रतबल दरगाह को आकार दिया था और उनके नाम पर कोई पत्थर (पट्टिका) नहीं है।

अब्दुल्ला का समर्थन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने किया। उन्होंने कहा कि दरगाह पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह रखना ईशनिंदा के समान है। उन्होंने दावा किया कि विरोध प्रदर्शन "प्रतीक चिन्ह के खिलाफ नहीं" बल्कि "मूर्ति पूजा" के खिलाफ था। माकपा नेता और विधायक एम.वाई. तारिगामी और मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ ने प्रदर्शनकारियों का पक्ष लिया।

इससे फिर यह सवाल उठता है कि 3 या 4 सितम्बर को किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई।

कुछ मुसलमानों ने प्रदर्शनकारियों की यह कहते हुए आलोचना की कि अशोक स्तंभ भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, राष्ट्रीय प्रतीक है, और मस्जिद के बाहर साइनबोर्ड पर इसकी उपस्थिति न तो नमाज़ में बाधा डालती है और न ही धर्म को नुकसान पहुँचाती है। दिलचस्प बात यह है कि अशोक चक्र हज पहचान पत्रों पर भी अंकित है। और भारतीय पासपोर्ट पर भी।

दिलचस्प बात यह है कि 8 सितंबर को सोशल मीडिया पर हज़रतबल दरगाह पर लगे एक हरे और सफ़ेद रंग के होर्डिंग की तस्वीर सामने आई। पीडीपी–भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान (2017–2022) लगाए गए इस होर्डिंग पर अशोक चिह्न अंकित है और प्रसाद योजना का संदेश लिखा है। यह केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय (2014–15) की एक पहल थी ऐतिहासिक महत्व के तीर्थ स्थलों के विकास के लिए। गूगल इमेजेज़ पर रिवर्स इमेज सर्च टूल से तस्वीर में छेड़छाड़ का कोई प्रमाण नहीं मिला।

आलोचकों का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति विरोध पूरी तरह से राजनीतिक है।

भारत के अल्पसंख्यकों (मुस्लिम) समुदाय के लोगों को खाड़ी के कुछ इस्लामी देश, जहां इस्लाम का जन्म हुआ था, से सीख लेनी चाहिए जो एक उदार धर्म का समर्थन कर रहे हैं। यह देश कट्टरपंथियों के आतंक और क्रूरता से अपने युवाओं को खींच रहे हैं एवं देश और दुनिया के सभ्य, सुसंस्कृत नागरिक बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्या कारण है कि भारत के मुसलमान इस दौर में पीछे रहे। ❑❑

Dainik Jagran, 8 September 2025
https://www-jagran-com/editorial/apnibaat-hazaratbal-shrine-row-controversy-over-ashok-chakra-sparks-outrage-24040345.html

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC: BKID-0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

वैज्ञानिक और दार्शनिक चेतना की गांठें खोलता है 'कालजयी भारतीय ज्ञान'

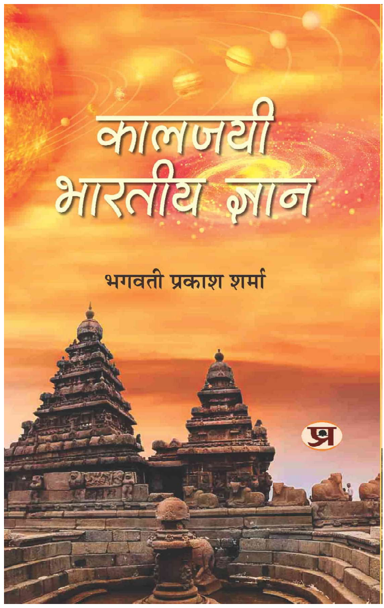

डॉ. भगवती प्रकाश शर्मा की पुस्तक "कालजयी भारतीय ज्ञान" भारतीय प्राचीन वाङ्मय और आधुनिक विज्ञान के मध्य सेतु का कार्य करती है और आधुनिक विज्ञान के अंतःसंबंधों को नए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक केवल प्राचीन भारत की बौद्धिक धरोहर के गौरव का आलाप नहीं करती, बल्कि वैज्ञानिक तर्कों और समकालीन अनुसंधानों के आलोक में उसे प्रमाणित करने का प्रयास भी करती है। इस दृष्टि से यह कृति एक ओर गहन शोधपरक दस्तावेज़ और दूसरी ओर सांस्कृतिक आत्मबोध का घोष है।

भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम

लेखक ने वैदिक साहित्य में निहित विविध ज्ञान–संपदा को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से विवेचित किया है। पुस्तक में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, श्याम ऊर्जा (डार्क एनर्जी), सौरमंडल और गुरुत्वाकर्षण के वैदिक उल्लेखों को वैज्ञानिक विमर्श से जोड़ा गया है। वैदिक ऋचाओं में निहित प्रकाश की गति, ग्रहण विज्ञान तथा ब्रह्मांडीय व्याख्याओं को वर्तमान वैज्ञानिक निष्कर्षों से तर्कसंगत रूप से जोड़ा गया है।

डॉ. भगवती प्रकाश शर्मा की पुस्तक "कालजयी भारतीय ज्ञान" केवल भारतीय गौरव गाथा नहीं है, बल्कि अनुसंधान और आलोचना दोनों की कसौटी पर परखी जा सकने वाली एक महत्त्वपूर्ण कृति है।
–नवनीत शर्मा

पुस्तक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसमें वैदिक, उपनिषदिक और पुराणोक्त ज्ञान के विविध आयामों को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर रखा गया है। लेखक ने प्रकाश की गति और सौरमंडल के रहस्यों जैसे विषयों का विश्लेषण करते हुए यह दर्शाने का प्रयास किया है कि भारतीय चिंतन केवल अध्यात्म और आस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें वैज्ञानिकता और विश्वदृष्टि भी निहित थी। उदाहरणार्थ, वैदिक साहित्य में वर्णित ग्रहण विधियों या गुरुत्वाकर्षण संबंधी उल्लेखों को आधुनिक वैज्ञानिक निष्कर्षों से साम्य स्थापित कर प्रस्तुत करना लेखक की व्याख्यात्मक दक्षता का परिचायक है। यहाँ आलोचना यह भी की जा सकती है कि ऐसे संदर्भों को आज के कठोर प्रायोगिक मानदंडों पर परखने की आवश्यकता है, अन्यथा वे केवल प्रतीकात्मक समानता बनकर रह जाते हैं।

वैदिक राजनीतिक और सामाजिक चिंतन

पुस्तक का दूसरा महत्वपूर्ण अध्याय वैदिक राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का पुनर्पाठ है। लेखक ने लोकतंत्र, गणराज्य, राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया, शपथ और शासन की मर्यादाओं की वैदिक विवेचना प्रस्तुत की है। यह कार्य निस्संदेह गौरवपूर्ण परंपरा को उद्घाटित करता है, किंतु साथ ही यह प्रश्न भी उपस्थित करता है कि इस परंपरा का ऐतिहासिक व्यावहारिक रूप कितना सुदृढ़ था और आधुनिक लोकतंत्र से उसका सरोकार

किस सीमा तक उचित ठहरता है। फिर भी, लेखक इस विमर्श के द्वारा यह स्पष्ट कर देते हैं कि भारतीय परंपरा में संगठित राजनीतिक संरचनाओं का विचार कितनी प्राचीनता से विकसित था।

वैज्ञानिक एवं दार्शनिक विमर्श

डॉ. शर्मा ने वेदों और उपनिषदों में वर्णित ज्ञान को केवल धार्मिक अनुश्रुति न मानकर उन्हें आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखा है। पुस्तक में उन्नत शब्द विज्ञान, गणितीय संकल्पनाओं तथा भौतिक और रासायनिक ज्ञान के संदर्भों की विवेचना की गई है।

ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में लेखक का दृष्टिकोण विशेष प्रकार की औपनिषदिक–वैज्ञानिक संवाद परंपरा को पुनर्जीवित करता है। शब्द विज्ञान, गणितीय प्रणालियाँ, औषधि–विज्ञान तथा खगोल संबंधी संदर्भों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर प्रस्तुत करना न केवल अनुसंधान की गहराई का परिचायक है बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक प्रासंगिकता भी प्रदान करता है। इसी श्रेणी में सूर्योपासना की वैश्विक परंपरा तथा अमेरिकी पुरावशेषों पर भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव संबंधित विमर्श आते हैं, जो भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रसार की ऐतिहासिकता को रेखांकित करते हैं।

हृदयगत स्मृति का विमर्श

पुस्तक का सबसे रोचक और शोधपरक खंड हृदय की स्मृति से संबंधित है। पारंपरिक मान्यताओं के साथ–साथ आधुनिक अनुसंधान के आधार पर लेखक यह सिद्ध करते हैं कि स्मृति केवल मस्तिष्क में ही नहीं, बल्कि हृदय तथा कोशिकाओं में भी संग्रहीत होती है। इसे सेलुलर मेमोरी कहा जाता है। पुस्तक में चार प्रमुख प्रकार की हृदयगत स्मृति का उल्लेख मिलता हैः पहली, एपिजेनेटिक मेमोरी – जीन अभिव्यक्ति और कोशिकीय कार्यप्रणाली से संबंधित। दूसरी, डीएनए मेमोरी – वंशानुगत स्मृति का स्थानांतरण। तीसरी, ज़ेड मेमोरी – ऊर्जा और सूचना का कोशिकाओं में दीर्घकालिक संग्रह एवं चौथी, प्रोटीन मेमोरी – अणुओं और प्रोटीन संरचनाओं में निहित स्मृति।

परंपरागत रूप से स्मृति और चेतना को मस्तिष्क से जोड़कर देखा जाता रहा है, किंतु लेखक ने आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर यह प्रतिपादित किया है कि स्मृति और व्यक्तित्व के लक्षण कोशिकीय स्तर पर, विशेषतः हृदय में भी संग्रहीत रहते हैं। एरिजोना विश्वविद्यालय के गैरी श्वाट्र्ज और लिंड रूसेक, हवाई विश्वविद्यालय के पॉल पियर्सन तथा ब्रूस लिप्टन जैसे वैज्ञानिकों के अन्वेषणों का उल्लेख इस विचार को विश्वसनीयता प्रदान करता है। हृदय प्रत्यारोपण के उपरांत प्राप्तकर्ताओं में दाताओं की प्रवृत्तियों और स्मृतियों का प्रकट होना इस अवधारणा को और ठोस आधार उपलब्ध कराता है। हृदय प्रत्यारोपण के बाद प्राप्तकर्ताओं में आए परिवर्तनों के उदाहरण लेखक ने बड़ी स्पष्टता से प्रस्तुत किए हैं। जैसे क्लेयर सिल्विया को प्रत्यारोपण के बाद बीयर और मिर्च खाने की आदत पड़ना, संगीत–प्रेमी दाता का हृदय पाने वाले व्यक्ति का अचानक शास्त्रीय संगीत के प्रति आकर्षित होना, या फिर एक हत्या की शिकार लड़की का हृदय पाने वाली महिला द्वारा हत्यारे की सही पहचान करना। ये सभी प्रकरण यह प्रमाणित करते हैं कि हृदय केवल रक्त प्रवाह का अंग नहीं है, बल्कि भावनाओं, स्मृतियों और चेतना का केंद्र भी है। ये सभी उदाहरण यह दर्शाते हैं कि हृदय केवल शारीरिक अंग न होकर भावनाओं और चेतना का भी केंद्र है।

समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यह विमर्श वैदिक चिंतन की उस धारणा की आधुनिक पुनर्स्वीकृति है, जिसमें हृदय को आत्मा और चेतना का स्थल माना गया है। किंतु आलोचना का एक अहम बिंदु यह भी है कि आधुनिक विज्ञान अब भी हृदयगत स्मृति संबंधी निष्कर्षों पर एकमत नहीं है। इन प्रयोगों और निष्कर्षों के ठोस और पुनरुत्पादनीय प्रमाण अभी सीमित हैं। ऐसे में लेखक की प्रस्तुति प्रेरणादायक तो है, किंतु इसे अंतिम वैज्ञानिक सत्य मान लेने में सावधानी अपेक्षित है। यही आलोचनात्मक विवेक इस कृति को और भी गंभीरता से पढ़े जाने योग्य बनाता है।

डॉ. शर्मा का एक मुख्य तर्क यह है कि उपनिषदों और पुराणों में वर्णित हृदयस्थित चेतना आज के वैज्ञानिक अनुसंधानों से मेल खाती है। मन और आत्मा का निवास स्थान केवल मस्तिष्क नहीं है, बल्कि हृदय भी चेतना का केंद्र है। यह विचार आधुनिक सेलुलर मेमोरी थ्योरी और न्यूरोकार्डियोलॉजी (हृदय–मस्तिष्क संबंध विज्ञान) से प्रमाणित होने लगा है।

हृदय प्रत्यारोपण के परिप्रेक्ष्य में यह अवधारणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी के बीच गहन अंतःसंबंध है।

विज्ञान और अध्यात्म के बीच अंतर्संबंध

समग्रतः "कालजयी भारतीय ज्ञान" केवल भारतीय गौरव गाथा नहीं है, बल्कि अनुसंधान और आलोचना दोनों की कसौटी पर परखी जा सकने वाली एक महत्त्वपूर्ण कृति है। इसमें भारतीय सांस्कृतिक ज्ञानधरोहर को आधुनिक विज्ञान से संवाद करने का साहसिक प्रयास किया गया है। यह पुस्तक उन सभी पाठकों के लिए प्रासंगिक है जो भारत की परंपरा को केवल अतीत का अवशेष न मानकर भविष्य की वैज्ञानिक और दार्शनिक दिशा के रूप में देखना चाहते हैं। ❑❑

डॉ. नवनीत शर्मा आर्थिक विषयों के चिंतक है एवं भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान में आस्था रखते हैं।

बहु–आयामी अवधारणा है महिलाओं का सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो महिलाओं और लड़कियों को रणनीतिक जीवन विकल्प बनाने और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने की शक्ति और नियंत्रण प्रदान करती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को जीवन के सभी पहलुओं में अवसरों, संसाधनों और अधिकारों तक समान पहुंच प्रदान करके लैंगिक विषमताओं को खत्म करना है।

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताओं को समाप्त करने की प्रक्रिया से है। इस शब्द ने 19 वीं शताब्दी में प्रमुखता प्राप्त की, सशक्तिकरण के साथ शक्ति को सक्षम करने या प्रदान करने के कार्य को दर्शाता है। सदियों से, महिलाओं को दुनिया भर में कमजोर लिंग माना जाता रहा है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी, महिलाओं को समान सामाजिक–आर्थिक स्थिति से वंचित रखा गया। इसे संबोधित करने के लिए, भारत सरकार और विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों दोनों ने समाज में महिलाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जिसे पांच प्रमुख रूपों में देखा जा सकता है– 1. सामाजिक सशक्तिकरण, 2. शैक्षिक सशक्तिकरण, 3. आर्थिक सशक्तिकरण, 4. राजनीतिक सशक्तिकरण एवं 5. मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ प्रगति के बावजूद, महत्वपूर्ण चुनौतियां विश्व स्तर पर महिला सशक्तिकरण में बाधा डालती हैं। कुछ प्रमुख कठिनाइयों की बात करें तो सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड जिसमें बाल विवाह, महिला जननांग विकृति और दहेज जैसी प्रथाएं अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में प्रचलित हैं। महिलाओं को अक्सर एक महत्वपूर्ण वेतन अंतर, व्यावसायिक अलगाव और वित्तीय संसाधनों और संपत्ति के स्वामित्व तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है।

> *नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार ने लड़कियों को हर क्षेत्र में तवज्जों देने के लिए 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' के नारे के तहत उनके उत्थान के लिए कई सकारात्मक कदम उठाये हैं।*
> **–स्वदेशी संवाद**

देश में लाखों लड़कियों को शिक्षा तक पहुंच से वंचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को अक्सर खराब स्वास्थ्य सुविधाओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित। इसी तरह लिंग आधारित हिंसा का मुद्दा है जिसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और मानव तस्करी शामिल हैं।

महिलाओं को अक्सर राजनीतिक नेतृत्व और निर्णय लेने वाले निकायों में कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, तस्करी और ऑनर किलिंग महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा को कमजोर करती रहती हैं।

(शेष पृष्ठ 35 पर ...)

या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धाविश्वासरूपेण संस्थिता...

शक्ति के नौ रूपों की उपासना का पर्व है शारदीय नवरात्र

भारत भूमि को विश्व में उस संस्कृति के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रकृति, शक्ति और तन–मन का संतुलन सर्वोच्च स्थान पर है। इस परंपरा के केंद्र में देवी शक्ति के विविध रूपों की पूजा और साधना का विशेष महत्व रहा है। इन्हीं महान पर्वों में से एक है 'शारदीय नवरात्र', जो आश्विन मास में प्रतिपदा तिथि से आरंभ होकर नौ दिनों तक चलता है और विजयादशमी को संपन्न होता है। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान का काल नहीं, बल्कि साधना, संयम और आत्मशुद्धि का उत्सव माना जाता है। सनातन परंपरा में वर्ष भर चार नवरात्रों का उल्लेख है। चौत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ। इनमें से चौत्र और शारदीय नवरात्र अधिक प्रसिद्ध और व्यापक रूप से मनाए जाते हैं। शारदीय नवरात्र शरद ऋतु की शुरुआत में आता है। यह केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव जीवन में संतुलन साधने का काल माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह नौ दिन देवी शक्ति के नौ रूपों की उपासना के लिए समर्पित होते हैं। कहा जाता है कि देवी सृष्टि में प्रेरणाशक्ति हैं और उन्हीं की साधना से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, साहस और विजय की प्राप्ति होती है।

नवरात्र के प्रत्येक दिन देवी के अलग–अलग स्वरूप की पूजा होती है। प्रथम दिन पर्वतराज हिमालय की शैलपुत्री की पूजा होती है,जिनसे श्रद्धा और स्थिरता का संदेश मिलता है। दूसरे दिन मॉ ब्रह्मचारिणी' की, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा चौथे दिन दिन मॉ कूष्मांडा पांचवे दिन स्कंदमाता'' छठे दिन माँ कात्यायनी' सातवें दिन माँ कालरात्रि आठवें मॉ महागौरी और नौवें और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मॉ के इन नौ रूपों की उपासना मानव जीवन को स्थिरता, संयम, साहस, नवसृजन, करुणा, धर्मरक्षा, भयमुक्ति, पवित्रता और सिद्धि से संपन्न होने के लिये की जाती है।

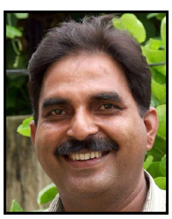

शारदीय नवरात्र केवल आस्था का पर्व ही नहीं, बल्कि जीवन को अनुशासित करने का अवसर भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऋतु परिवर्तन के समय उपवास और सात्विक आहार शरीर को स्वास्थ्य देता है।

– संजय सक्सेना

शारदीय नवरात्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू व्रत, उपवास और संयम है। उपवास केवल अन्न का त्याग ही नहीं, बल्कि विषय–वासना और नकारात्मक भावनाओं से भी दूरी बनाने का साधन माना गया है। पारंपरिक रूप से श्रद्धालु इस अवधि में फलाहार करते हैं और माँ दुर्गा को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद का सेवन करते हैं। धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि इस समय मनुष्य की इच्छाशक्ति और मानसिक दृढ़ता को शक्ति मिलती है। साथ ही, शरीर को भी शुद्ध करने के लिए यह उपवास सहायक होता है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन के समय साधारण भोजन की अपेक्षा हल्का और सात्विक आहार स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।

नवरात्र के बाद दशम दिन 'विजयादशमी' मनाई जाती है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इसी दिन भगवान राम ने रावण पर विजय पाई थी। विजयादशमी इसलिए केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह संदेश देता है कि अंततः सत्य की ही विजय होती है।

बहरहाल, देश के विभिन्न हिस्सों में शारदीय नवरात्र अलग–अलग रूपों में मनाया जाता है। उत्तर भारत के मंदिरों में सप्तशती पाठ और अखंड दुर्गा पूजा की परंपरा है। बंगाल और पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा भव्य पंडालों, मूर्ति स्थापन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ होती है। गुजरात में गरबा और डांडिया की विशेष परंपरा रही है, जहाँ स्त्री–पुरुष शक्ति स्वरूपा माँ की आराधना करते हुए नृत्य में भाग लेते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में रामलीला और रावण–दहन का आयोजन होता है। इन सभी रूपों में एक ही भाव छिपा होता है बुराई पर अच्छाई की विजय और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार।

शारदीय नवरात्र केवल आस्था का पर्व ही नहीं, बल्कि जीवन को अनुशासित करने का अवसर भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऋतु परिवर्तन के समय उपवास और सात्विक आहार शरीर को स्वास्थ्य देता है। ध्यान और जप मनःशांति प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह पर्व आत्मशुद्धि और ईश्वर से एकात्म होने का उत्तम समय है। साधना और उपासना का यह क्रम मनुष्य को भीतर से मजबूत करता है और जीवन की कठिनाइयों से जूझने का साहस देता है। शारदीय नवरात्र केवल नौ दिनों का धार्मिक आयोजन भर नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। यह पर्व व्यक्ति को आत्मसंयम, आध्यात्मिक साधना और सांस्कृतिक समृद्धि का संदेश देता है। नौ दिनों की भक्ति और साधना के पश्चात विजयदशमी का उत्सव हर मानव को यह प्रेरणा देता है कि चाहे जीवन में कितने ही संघर्ष क्यों न आएं, सत्य, धर्म और सद्गुण की विजय अवश्य होती है।❑❑

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

(पृष्ठ 33 से जारी...)

बहु–आयामी अवधारणा है महिलाओं का सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण की राह में आ रही बाधाओं को दूर करना केंद्र की वर्तमान सरकार की प्राथमिकता में है। नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार ने लडकियों को हर क्षेत्र में तवज्जों देने के लिए 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' के नारे के तहत उनके उत्थान के लिए कई सकारात्मक कदम उठाये हैं। यही कारण है कि 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' योजना बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में गिरावट को संबोधित करती है और इसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है। यह सामाजिक मानसिकता को बदलने और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना – यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जो अपने पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मां और नवजात शिशु दोनों के लिए उचित पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।

वन–स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना – ये केंद्र सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता और सहायता प्रदान करते हैं। सेवाओं में चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय और मनोवैज्ञानिक परामर्श शामिल हैं।

महिला शक्ति केंद्र योजना – इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह उनके लिए कौशल विकसित करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंचने और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का समर्थन – यह कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार सहायता प्रदान करता है, जैसे कृषि, हथकरघा और हस्तशिल्प। यह उन्हें कौशल हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। ❑❑

स्वदेशी अपनाने से ही होगा राष्ट्र का उत्थानः आर सुंदरम

स्वदेशी का मतलब सिर्फ कुछ उत्पादों के देसी या विदेशी मूल के होने के कारण उपयोग करना या नहीं करना तक सीमित नहीं है स्वदेशी का मतलब उन उत्पादों का और तौर तरीकों का उपयोग करना है जो व्यक्ति समाज और देश के हित में हो यह बात स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक आर सुंदरम ने कहीं दयानंद महाविद्यालय में आर्थिक समूह के कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए सुंदरम ने कहा कि स्वदेशी जरूरत के आधार पर चलने वाली जीवन शैली को प्रेरित करता है और उपभोग वार्ड पर आधारित जीवन शैली को ना करता है अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वदेशी बाहरी देशों के खिलाफ जंग नहीं बंद अर्थव्यवस्था बनने का मिशन नहीं जरूर आधारित स्वदेशानुराग है स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल ने बताया कि वर्तमान समय अमेरिकी टैरिफ की आपदा नहीं है यह भारतवासियों के लिए एक अवसर है जिसमें वह अपनी अर्थव्यवस्था में स्वदेशी को अपना कर भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बन सकता है वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का बाजार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यही बाजार स्वदेशी तकनीक पर विकसित होकर विश्व के दादागिरी करने वाले देश को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है विकल्प केवल एकमात्र स्वदेशी है स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंगठक सतीश कुमार ने बताया कि आज भारत अमेरिका के टैरिफ के दबाव में नहीं है भारत सरकार ने विश्व के विकसित देश अमेरिका के टैरिफ का मुंह तोड़ जवाब दिया है और यह तभी संभव हो पाया है जब देश का प्रत्येक नागरिक अपने उपयोग में आने वाली वस्तुओं का स्वदेशी विकल्प चुनकर उपयोग करने लगा है इस देश का प्रत्येक नागरिक अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ स्वदेशी वस्तुओं को अपना कर भारत के विकास में सहयोगी बन सकता है दयानंद महाविद्यालय में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में अखिल भारतीय अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को सकारात्मक ऊर्जा के साथ स्वदेशी का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए आह्वान किया महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने स्वदेशी जागरण मंच के इस मुहिम की सराहना करते हुए मंच के अधिकारियों को इस पूर्णिया कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया प्रांत संयोजक चित्तौड़ प्रांत डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि अखिल भारतीय अधिकारियों ने बुधवार को राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी जागरण मंच के डिजिटल फॉर्म को बनाने वाली टीम के साथ बैठक कर उनके कार्य की सराहना की राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी जागरण मंच की ओर से युवाओं को जोड़ने के लिए माय एसबीए मेरा स्वालंबी भारत अभियान एप्लीकेशन का निर्माण करने वाली टीम को बधाई दी स्वदेशी जागरण मंच की आईटी सेल के प्रमुख प्रसिद्ध उद्योगपति राधेश्याम चोयल के कार्यालय पर आईटी सेल के सभी युवा कार्यकर्ताओं के काम को सराहा।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर संघ चालक खाजू लाल, सहसंघ चालक करण सिंह जोधा, स्वदेशी जागरण मंच सह प्रांत संयोजक डॉ ज्योति वर्मा, राष्ट्र सेविका समिति के क्षेत्र अधिकारी लीलामणि, उद्योगपति राधेश्याम चोयल, अजमेर विभाग संयोजिका डॉक्टर सुचित्रा राठौर, विभाग महिला प्रमुख गरिमा गोयल, विभाग सहसंयोजक डॉक्टर कुलदीप सिंह, विभाग संयोजक दिलीप कुमार चौहान, पूर्णकालिक कार्यकर्ता राकेश, डॉक्टर महावीर प्रसाद, डॉक्टर दीप सिंह, डॉक्टर सुभाष सिंघल, डॉ राजश्री बंसल, डीआर सोनिया जोसेफ, डॉ एच के सेन, डॉ महावीर प्रसाद, महानगर संयोजक योगेंद्र सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को स्वदेशी का संकल्प दिलवाया और इसी संकल्प को भारत के जन–जन तक पहुंचाने का आग्रह किया जिससे स्वदेशी जागरण मंच का यह अभियान जन–जन तक पहुंचे और भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बने कार्यक्रम का प्रारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया महाविद्यालय प्राचार्य ने स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय अधिकारियों का केसरिया ऊपर ना उड़ा कर स्वागत और अभिनंदन किया मंच का संचालन डॉ एच के सेन ने किया।

स्वदेशी उत्पाद खरीदना ही टैरिफ का सही जवाबः कश्मीरी लाल

स्वदेशी जागरण मंच की राजस्थान क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक गुरूवार को स्टील नगर, जोधपुर में आयोजित हुई। स्वदेशी जागरण मंच राष्ट्रीय संयोजक और अर्थशास्त्री आर सुंदरम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी स्वदेशी के सबसे बड़े ब्रांड एंबेसडर है। उन्होंने कहा की 1998 में भी पोखरण परीक्षण के बाद अमेरिका, यूरोप, जापान सहित कई देशों ने भारत पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए थे। जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने अपनी स्वयं की कई तकनीक को विकसित कर इन प्रतिबंधों का डटकर सामना किया था। अभी के अमेरिकी टैरिफ का भी असर हम अपने विशाल घरेलू बाजार और अन्य विदेशी बाजारो के द्वारा बेअसर कर सकते हैं। मंच के राष्ट्रीय संगठन कश्मीरी लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार की कई मजबूरियां हो सकती है, लेकिन हम देशवासियों की कोई मजबूरी नहीं है। हम मार्केट से केवल स्वदेशी ब्रांड की वस्तुओं को ही खरीदें जिससे इस टैरिफ का सामना किया जा सके। मंच के राष्ट्रीय संगठक सतीश कुमार ने कहा कि पूरे देश भर में स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबी अभियान चलाया जा रहा है और स्वदेशी शोध संस्थानों के माध्यम से देश में आने वाली विभिन्न आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के निराकरण का प्रयास चल रहा है। वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए हमें अपने जनसंख्या नियंत्रण के नियमों को भी बदलने की आवश्यकता है। जिससे देश में युवा आबादी बढ़े और देश की जीडीपी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

बैठक को अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख डॉ राजकुमार चतुर्वेदी और क्षेत्रीय विचार प्रमुख अनिल वर्मा प्रांत संयोजक प्रमोद पालीवाल ने भी संबोधित किया। स्वदेशी जागरण मंच के जोधपुर प्रांत के प्रचार प्रमुख मिथिलेश झा और विभाग संयोजक प्रेम पालीवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किये। क्षेत्रीय बैठक में जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ प्रांत के 60 स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आगामी 15 और 16 सितंबर को नागपुर में पूरे देश भर के व्यापारियों और रिटेलरों के संगठनों की बैठक स्वदेशी जागरण मंच के सहयोग से आयोजित होगी। बैठक का संचालन क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर सतीश आचार्य ने किया।

वैश्विक शक्तियां कर रही भारतीय हितों को नुकसानः सतीश कुमार

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह–संगठक सतीश कुमार ने कहा है कि वैश्विक महाशक्तियां अपने स्वार्थों के कारण भारतीय आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं। अमेरिका लगातार टैरिफ बढ़ाकर भारत के हितों पर आघात कर रहा है और अपनी शर्तें भारत पर थोपना चाहता है, जो देशहित में स्वीकार्य नहीं है। वे स्वदेशी जागरण मंच जयपुर प्रांत की और से स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित फरिश्ता एक्सपोर्ट्स में उद्यमियों की महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते हमें दैनिक जीवन की वस्तुओं की सूची बनाकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा और स्वदेशी उत्पादों को अपनाना होगा। जहां तक संभव हो, उद्योग धंधों में भी स्वदेशी मशीनों एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थानीय उत्पादों और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा विदेशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भरता घटेगी। सतीश कुमार ने कहा कि अमेरिका, चीन, तुर्की और अजैरबान जैसे देशों का रवैया कभी भारत समर्थक नहीं रहा है । इन देशों ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है, इसलिए इनको आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से दंडित करना आवश्यक है। इसका एकमात्र विकल्प स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और खरीद–फरोख्त को बढ़ावा देना है।

इस अवसर पर प्रांत संयोजक सुरेंद्र कुमार नामा, प्रांत समन्वयक लोकेन्द्र सिंह, प्रांत सह–समन्वयक दिनेश कुमार शर्मा, विभाग सह– संयोजक राम प्रसाद शर्मा, जयपुर महानगर संयोजक शंभू सिंह, सांगानेर महानगर संयोजक शेर सिंह सहित अनिरुद्ध जोशी, पुरुषोत्तम जोशी, महेश जी कालूवास तथा सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया के 35 उद्यमी उपस्थित थे।

स्वदेशी अपनाने से भारत बनेगा विकसित राष्ट्रः प्रपन्नाचार्य महाराज

भगवान श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट के रामघाट स्थित बड़े मठ में स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वालंबी भारत अभियान की बैठक संपन्न हुई जिसकी अध्यक्षता महंत वरुण प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कानपुर प्रांत के संयोजक सुदीप खरे, विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वालंबी भारत अभियान झांसी महानगर के समन्यवक प्रवीण अग्निहोत्री उपस्थित रहे। बैठक में सशक्त एवं विकसित

भारत के निर्माण के लिए स्वेदशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने पर जोर देते हुए स्वदेशी जागरण मंच के कानपुर प्रांत के संयोजक सुदीप खरे द्वारा कई नवीन दायित्वों की घोषणा की गई। जिसमें संगठन की जिला समन्यवक समता तिवारी को बनाया गया। स्वदेशी जागरण मंच का जिला संयोजक गीता तिवारी को बनाया गया। इसके अलावा जिला सहसमन्वयक कृष्ण कुमार, सह समन्वयक विनीत, महिला सह समन्वयक प्रिया मिश्रा व रेखा गुप्ता, विद्यार्थी प्रमुख पंकज, छात्र प्रमुख पीलू सिंह, सह विद्यार्थी प्रमुख पंकज मिश्रा, सह छात्रा प्रमुख का दायित्व गरिमा वर्मा को सौपा गया।

इस मौके पर मुख्य अतिथि श्री खरे ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच की बैठक का उद्देश्य भारत को सशक्त राष्ट्र बनाना एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेश द्वारा निर्मित वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना है। उन्होने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच की टीम हर जिले में व्यापारियों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को बेचने के लिए प्रेरित करने का काम कर रही है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे महंत वरुण प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने कहा कि स्वेदी के प्रोत्साहन से ही भारत सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत से अमेरिका जैसे पक्तिपाली देश मनमाना टैरिफ लगाकर भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का कुचक्र रच रहे है। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों के प्रभाव को कम करने के लिए सभी को स्वदेशी उत्पादों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा तभी स्वावलम्बी आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार होगी। जिला समन्वयक ममता तिवारी ने कहा कि स्वदेशी अपनाने से ही पीएम मोदी व योगी का भारत समृद्ध राष्ट्र बनेगा। बैठक का संचालन स्वदेशी जागरण मंच चित्रकूट के जिला संयोजक राजेश कुमार पाण्डेय ने किया।

स्वदेशी से ही होगी विश्व पटल पर भारत की जयकारः कश्मीरी लाल

स्वदेशी जागरण मंच की पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की बैठक में बृज, मेरठ एवं उत्तराखण्ड प्रान्त के प्रतिनिधि, आर्य महिला पी.जी. कालेज में एकत्रित हुये। स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान, जिला स्वावलंबन केन्द्र, स्वदेशी मेला, स्वदेशी उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन, युवा एवं महिला तथा वरिष्ठ नागरिक आयाम सहित 15 विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल ने कहा कि वर्तमान समय में राष्ट्र में स्वदेशी का एक वातावरण बना हुआ। अमेरिका द्वारा जो चुनौती भारत के नागरिकों को दी गयी है। उससे हम सभी भारतीय स्वदेशी एवं राष्ट्रवादी विचारधारा को स्वीकार करने एवं जाग्रत करने से ही हम सभी भारतीय सुरक्षित रहेगें।

उन्होनें कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देशन करते हुये कहा की सभी कार्यकर्ताओं की व्यवहार कुशलता एवं कार्य के प्रति लगन से ही देश में स्वदेशी का वातावरण मजबूत होगा।

अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख डा. राजीव कुमार ने कहा कि भारत को आर्थिक रूप से सुरक्षित, समृद्ध और स्वावलंबी बनाने के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना होगा की अपने घर पर परिवार, व्यापार में स्थानीय और स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देगें। चाइनीज, तुर्की, अमेरिका और अन्य विदेशी कम्पानियों के उत्पाद के प्रयोग से बचेंगे। स्वदेशी क्रय विक्रय, स्वदेशी भाषा, वेषभूषा, उत्सव पद्धति आदि पर आग्रह रखेंगे। गुणवत्ता पूर्ण रोजगार उद्यमिता से आता है इसका सब प्रकार से प्रचार प्रसार करेंगे। " हर घर स्वदेशी .... हरयुवा उद्यमी" के विचार को जन–जन तक पहुँचाने के लिए अथक प्रयास करने होंगे। विश्व पटल पर भारत जयकार कराने हेतु सब प्रकार के प्रयत्न करेंगे।

बैठक में उत्तराखण्ड प्रान्त के विपिन, सुशील कुमार, नितिन जोशी, मती श्वेता तिवारी, सज्न टम्टा, मेरठ प्रान्त के प्रशान्त महर्षि, ए.के. अग्रवाल, कुलदीप सिंह एवं बृज प्रान्त के सुशील चैहान, डा. गुलशन रस्तोगी, राजेश कुमार, डा. एम. पी. सिंह चैहान, डा. रानू दुबे, अरविन्द मिश्रा, डा. उमेश भारती, मनोज अग्रवाल, कैलाश, चन्द्रप्रकाश, राजभूषण जौहरी, पंकज टण्डन, डा. आशीष गोयल, देवेन्द्र सिंह राठौर, राकेश कमार मिश्र (अनावा), डा. अनुराग अग्रवाल, अवधेश कुमार दीक्षित, राधारमण मिश्रा, धर्मपाल वर्मा, नरेन्द्रपाल सक्सेना, निश्चय त्रिवेदी, नीरज कश्यप, राकेश वर्मा, सुधीर आदि उपस्थित रहें।

जब भी बाजार जाएंगे, स्वदेशी ही लाएंगे के नारे को मिला समर्थन

नेताजी सुभाष महाविद्यालय अभनपुर में स्वदेशी जागरण मंच व स्वावलंबी भारत अभियान के संयुक्त तत्वावधान में स्वदेशी उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. व्ही. के. मिश्रा ने किया। मुख्य वक्ता डॉ. शीला शर्मा ने भारत की प्राचीन व धूमिल होती परंपराओं व संस्कृति के सरंक्षण के साथ स्वदेशी परंपराओं व स्थानीय बाजार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। दिग्विजय भाकरे एवं श्याम शर्मा ने विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उपस्थित लोगों ने 'जब भी

बाजार जाएंगे, स्वदेशी सामान लाएंगे' के नारे को आत्मसात किया। इस मौके पर स्वरोजगार में जुटे 10 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन प्रमाण पत्र दिए गए। इस अवसर पर प्राध्यापकगण व विद्यार्थी उपस्थित रहे।

उमा सिंह इंटर कॉलेज मानपुर में स्वदेशी जागरूकता अभियान

देश को विकसित राष्ट्र बनाने में हम सब लोगों का महती कर्तव्य है। वैश्विक दादागिरी से निपटने के लिए स्वदेशी को प्रयोग में लाना आवश्यक हो गया है। स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबन की भावना विकसित करने के लिए जन जागरण अभियान चला रहा है, जिसमें आप लोगों की सहभागिता से देश को नए आयाम तक पहुंचाया जा सकता है।

उक्त विचार उमा सिंह इंटर कॉलेज मानपुर में आयोजित स्वदेशी जागरूकता अभियान कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रांत समन्वयक हर्षवर्धन सिंह ने व्यक्त किए। उनके साथ राजीव जी पूर्णकालिक स्वदेशी जागरण मंच निवासी अयोध्या और जिला संयोजक अवनीश द्विवेदी उपस्थित रहे। उमा सिंह इंटर कॉलेज मानपुर में आयोजित स्वदेशी जागरूकता अभियान कार्यक्रम में छात्र–छात्राओं को संबोधित करते हुए राजीव जी ने बताया कि स्वदेशी वस्तुओं को हर घर परिवार में प्रयोग में लाने की आवश्यकता है इसके लिए स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी, चीनी और तुरकिये की वस्तुओं को ना खरीदें और स्वदेशी अपनाएं। प्रांत समन्वयक हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उद्यमिता से देश को स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। आप सभी लोग इस सूची के हिसाब से अपने देश में ही बनी वस्तुओं को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग में लाएं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके विकसित राष्ट्र बनाने और स्वावलंबन भारत बनाने में अहम भूमिका निभाएं। जिला संयोजक अवनीश द्विवेदी ने इस अवसर पर उपस्थित छात्र व छात्राओं, शिक्षकों को स्वदेशी संकल्प दोहरा कर शपथ दिलाई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक तेज प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य सुप्रिया ठाकुर और शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

स्वदेशी अपनाने से ही देश बनेगा स्वावलंबी

अर्थ नीति पर पूरे देश में काम करने वाला स्वदेशी जागरण मंच की पश्चिम बर्द्धमान जिला कमेटी द्वारा भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय बर्नपुर में संवाददाता सम्मेलन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय संघर्ष वाहिनी प्रमुख अन्नदा शंकर पाणिग्रही ने कहा कि आज अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर जो टैरिफ लगाया, उससे हमें एक अवसर मिला है कि हम स्वावलंबी बने। जब हम ब्रांड के नाम पर अपनी पहचान को दिखाना छोड़कर स्वदेशी वस्तु का व्यवहार करने लगेंगे तभी हम अपने बाजार को बचाकर बेरोजगारी को दूर कर पाएंगे और भारत को पुनः विश्व गुरु बना पाएंगे।

15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में स्वदेशी वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए देश के व्यापारी और ग्राहकों से अपील की। उन्होंने बताया कि जब हम अपने जीवन में स्वदेशी का महत्व देंगे तभी हम देश को स्वावलंबी और समृद्ध बना सकते हैं। इस दौरान मध्य बंगाल प्रांत के विचार विभाग प्रमुख डा. जयदीप बनर्जी, जिला संयोजक संग जयप्रकाश सिंह, सह संयोजक मुख संदीप बर्णवाल, आसनसोल दक्षिण रक के नगर संयोजक संतोष सिंह, सह शि संयोजक अवधेश कुमार चौरसिया, आसनसोल उतर के नगर संयोजक पंकज बर्णवाल, मध्य बंगाल प्रचार प्रमुख शंकर मेहता के साथ जिले के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

स्वदेशी जागरण मंच ने फूंका डोनाल्ड ट्रंप का पुतला

स्थानीय बस स्टैंड (रेवती) पर स्वदेशी जागरण मंच ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ट्रंप का पुतला दहन कर अमेरिकी नीतियों और उत्पादों का विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी सामानों का बहिष्कार करो, तुर्की बाय काट, और अजरबैजान बाय काट जैसे नारों वाले पोस्टर, बैनर और तख्तियां लहराई। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए गए, जिससे पूरा क्षेत्र गूंज उठा। स्वदेशी जागरण मंच के सदस्यों ने स्थानीय लोगों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और विदेशी, खासकर अमेरिकी सामानों का पूर्ण बहिष्कार करने की अपील की। मंच के प्रमुख कार्यकर्ता भोला ओझा ने कहा कि भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी नीति से डरने वाली नहीं है।

भारत ने 50 प्रतिशत टैरिफ के जवाब में डाक सहित अन्य व्यापारिक समझौतों को रद्द कर मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने दावा किया कि भारत के पारंपरिक मित्र देशों जैसे रूस, फ्रांस और चीन का समर्थन प्राप्त है, जिसके चलते अमेरिकी टैरिफ का भारत पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री ओझा ने चेतावनी दी कि इस तरह की धोखेबाजी के लिए अमेरिका को ही आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। मौके पर धनंजय, रमाशंकर, निरंजन, माझील बाबा आदि मौजूद रहे। ❑❑

उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम

सचित्र झलक

बर्नीहाट, असम-मेघालय सीमा

नलबाड़ी, उत्तर असम

उत्तरी असम

पटना, बिहार

त्रिपुरा

रायपुर, छत्तीसगढ़

जयपुर

असम

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 सितंबर 2025
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2024-26
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी संकल्प यात्रा

सचित्र झलक

दार्जिलिंग, प.बंगाल

देवघर, झारखंड

करीम नगर, तेलंगाना

मेदनीपुर, दक्षिण बंग

इम्फाल, मणिपुर

शाहजहांपुर, प.उ.प्र.

मणिपुर

अजमेर

तरनतारन, पंजाब

ग्वालियर, म.प्र.

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती